

जनत विज्ञान

छत्तीसगढ़ को गर्त में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन?

रमन सरकार ने 15 सालों में 41 हजार करोड़ तो
भूपेश सरकार ने साढ़े तीन साल में 51 हजार करोड़ का लिया कर्ज

विजया:





प्रेरणा स्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन

पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	श्रीवास्तव,
गोवा ब्यूरो चीफ	अमित राय
गुजरात ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
दिल्ली ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
पटना संवाददाता	विजय वर्मा
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	सौरभ कुमार
बंदेलखण्ड संवाददाता	वेद कुमार
विधिक सलाहकार	रफत खान

विजया पाठक	आनन्द मोहन
समता पाठक	श्रीवास्तव,
अर्चना शर्मा	अमित राय
समीर शास्त्री	अजय सिंह
बिन्देश्वरी पटेल	गौरव सेठी
मणिशंकर पाण्डेय	विजय वर्मा
आनन्द मोहन	सौरभ कुमार
श्रीवास्तव,	वेद कुमार
अमित राय	रफत खान
अजय सिंह	एडवोकेट
गौरव सेठी	राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायक विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज

एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार

बीड़ीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17,

शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया

पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय

रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख

एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.in

छत्तीसगढ़ को गर्त में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन?

रमन सरकार ने 15 सालों में 41 हजार करोड़ तो
भूपेश सरकार ने साढ़े तीन साल में 51 हजार करोड़ का लिया कर्ज

विजया ।



(पृष्ठ क्र.-6)

- श्रीलंका का सबक 42
- बाढ़ आपदा को रोकने में सरकारें नाकाम हैं? 45
- बीजेपी के लिए क्या तुरूप का इक्का साबित होंगे धनगढ़? 52
- कांग्रेस ने बिछा दी 2023 की बिसात 54
- There is a fundamental error in th thinking.....61





चंडाल चौकड़ी के सामने बेबस, लाचार भूपेश बघेल



द्वौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर साधे हैं कई निशाने

द्वौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने इन्हें राष्ट्रपति बनाकर कई तीर साध लिये हैं। कह सकते हैं कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात है। बीजेपी ने आदिवासी चेहरे पर अपनी सेंध लगाने की कोशिश है। इसके साथ ही बीजेपी ने विपक्ष में सेंध लगाने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। क्योंकि चुनाव के दौरान देखा गया है कि कई राज्यों में क्रास वोटिंग हुई थी। यही बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक आदिवासी को सर्वोच्च य पद पर बिठाकर बीजेपी ने देश के एक बड़े वोटबैंक को अपनी ओर खींचा है। यह वहीं वोटबैंक है जो कांग्रेस का वोटबैंक माना जाता रहा है।

गौरतलब है कि द्वौपदी मुर्मू पहली आदिवासी नेता हैं, जो संविधान में सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। द्वौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के पीछे भाजपा ने विपक्षी दलों को 2024 से पहले 2022 में ही ट्रेलर दिखा दिया है। द्वौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के पीछे भाजपा ने विपक्ष को सियासी बाजीगरी में उलझा दिया है। आजादी के बाद यह मौका है जब देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिला है। इसका श्रेय भाजपा को जाता है, जिसने आदिवासी नेता को देश के संविधान में सर्वोच्च पद पर पहुंचा दिया। मुर्मू की ताजपोशी के साथ ही विपक्षी एकता के साथ खेला भी हुआ है। द्वौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाकर भाजपा ने साल 2024 के लिए बड़ी तैयारी का आगाज कर दिया है। इसे भाजपा के ट्रेलर के रूप में देखा जा सकता है। आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वाली मुर्मू को सर्वोच्च पद पर बैठाकर भाजपा ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में द्वौपदी मुर्मू को उतारते ही भाजपा ने चुनाव परिणाम से पहले ही आधी जंग जीत ली थी। मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। ऐसे में विपक्ष लाख कोशिश के बावजूद भी अपनी एकता को बरकरार नहीं रख पाया। झारखंड में मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस से गठबंधन है। लेकिन फिर भी जेएमएम ने मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। राष्ट्रपति चुनाव से पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के बयान से ही विपक्षी एकता के दावों की पोल खुल गई थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर भाजपा उनसे द्वौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए कहती तो वो मान जाती। यहां ये गौर करने वाली बात है कि ममता बनर्जी ने ही विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा था। टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूरी बनाने का फैसला लिया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने मार्गेंट अल्चा के नाम के लिए ममता बनर्जी से चर्चा नहीं की थी। द्वौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान भाजपा की ओर से विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की घोषणा के बाद किया गया था। इसके बाद भी विपक्षी दलों में से कई पार्टियों ने द्वौपदी मुर्मू को समर्थन किया। बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अकाली दल, शिवसेना, तेलगु देशम पार्टी समेत कई ऐसे दलों ने द्वौपदी मुर्मू को समर्थन किया, जो एनडीए का हिस्सा नहीं हैं।

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ को गर्त में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन?

रमन सरकार ने 15 सालों में 41 हजार करोड़ तो
भूपेश सरकार ने साढ़े तीन साल में 51 हजार करोड़ का लिया कर्ज



“ छत्तीसगढ़ आज अराजकता और अंधकार की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश की भूपेश सरकार ने इसे गर्त में पहुंचा दिया है। पौने चार साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि चारों ओर भ्रष्टाचार, भय और आक्रोश का माहौल है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तमाशबीन मुख्यमंत्री की तरह छत्तीसगढ़ को बर्बाद होते देखने को मजबूर हो रहे हैं। वैसे एक समय था जब भूपेश बघेल ने विपक्ष में रहते हुए एक कददावर, साहसी और निडर नेता के रूप में अपने आपको स्थापित किया था। लेकिन जैसे ही वह सत्ता के सिंहासन पर बैठे उनका पूरा का पूरा आभा मंडल बिखर गया। यह भी सच है कि मुख्यमंत्री बनने के शुरुआती दिनों में भूपेश बघेल अपनी पुरानी शैली में ही थे। धीरे-धीरे जैसे ही उनके आसपास चाटुकारों और भ्रष्ट अफसरों का मार्गदर्शन मिला उनका रवैया और रुतबा दोनों बदल गए। राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों का मानना है कि भूपेश बघेल के व्यवहार में आए बर्ताव के पीछे उनके चारों ओर मंडरा रही चंडाल चौकड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। यह चंडाल चौकड़ी आज पूरे प्रदेश में कुख्यात है। इस चौकड़ी में 02 पत्रकार विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग, एक प्रमोटी आईएएस अफसर अनिल दुटेजा और उप-सचिव सौम्या चौरसिया हैं। प्रदेश की पूरी राजनीति इन चारों को इर्द-गिर्द घूम रही है। इस चौकड़ी के कारण ही आज प्रदेश की दुर्दशा हो रही है और भूपेश बघेल की छबि धूमिल हो रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आज भी लोकप्रियता कम नहीं हुई है लेकिन चंडाल चौकड़ी के कहने पर होने वाले कारनामे उन्हें बदनाम करने में कोई कार कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ”

विजय पाठक

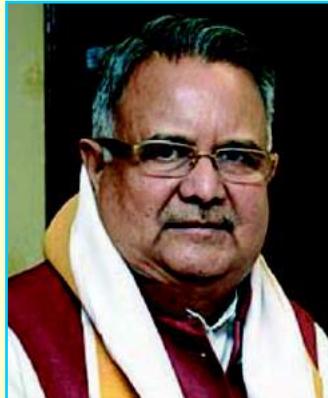
खैर, कारण कोई भी रहे हो लेकिन इतना कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़वासी कभी भी सरकार और सत्ता के कारण इतने परेशान नहीं हुए जितने आज की स्थिति में हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं।

दुष्कर्म, छेड़छाड़, लूट, हत्या, चाकूबाजी, डकैती की गंभीर घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। शांति का टापू कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। प्रदेश में लोग सुरक्षित नहीं हैं। अज्ञात हमलावरों द्वारा लूटपाट की घटनाएं, हत्या के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ के नाम से जाना जा रहा है। इन

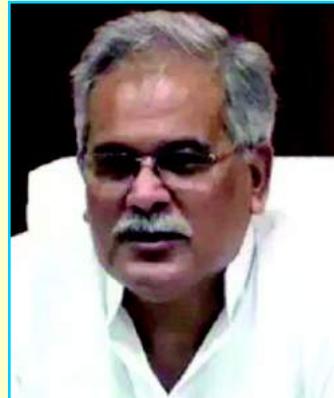
सबके पीछे भूपेश सरकार की कानून व्यवस्था पर नाकामी नजर आ रही है। पत्रकारों पर अत्याचार चरम पर है। उन्हें अपनी मर्जी से लिखने या बोलने की आजादी से बंचित कर दिया है। यदि पत्रकार अपनी बातें करता भी है तो उसे कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य राज्य में आदिवासियों के

रमन सरकार ने 15 सालों में 41 हजार करोड़ तो भूपेश सरकार ने साढ़े तीन साल में 51 हजार करोड़ का लिया कर्ज

देश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार के मामले में अबल छत्तीसगढ़



छत्तीसगढ़ को वैसे तो गरीब राज्य कहा जाता है। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इसे देश का ऐसा सम्पन्न राज्य बना दिया है जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। इस मामले में सरकार का एक ही एजेण्डा है कर्ज लो और भ्रष्टाचार करो। जांच पड़ताल तो सरकार के ही हाथों में हैं। लिहाजा जैसा राज्य, वैसी प्रजा की तर्ज पर, जैसे मुख्यमंत्री, वैसी उनकी शैली। भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ ने जो कुछ्याति अर्जित की है उससे इस राज्य की न केवल गरिमा हनन हुई है बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में यह राज्य काफी सम्पन्न नज़र आता है। अगर आकड़ों पर गौर करें तो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने अपने 15 सालों के कार्यकाल में



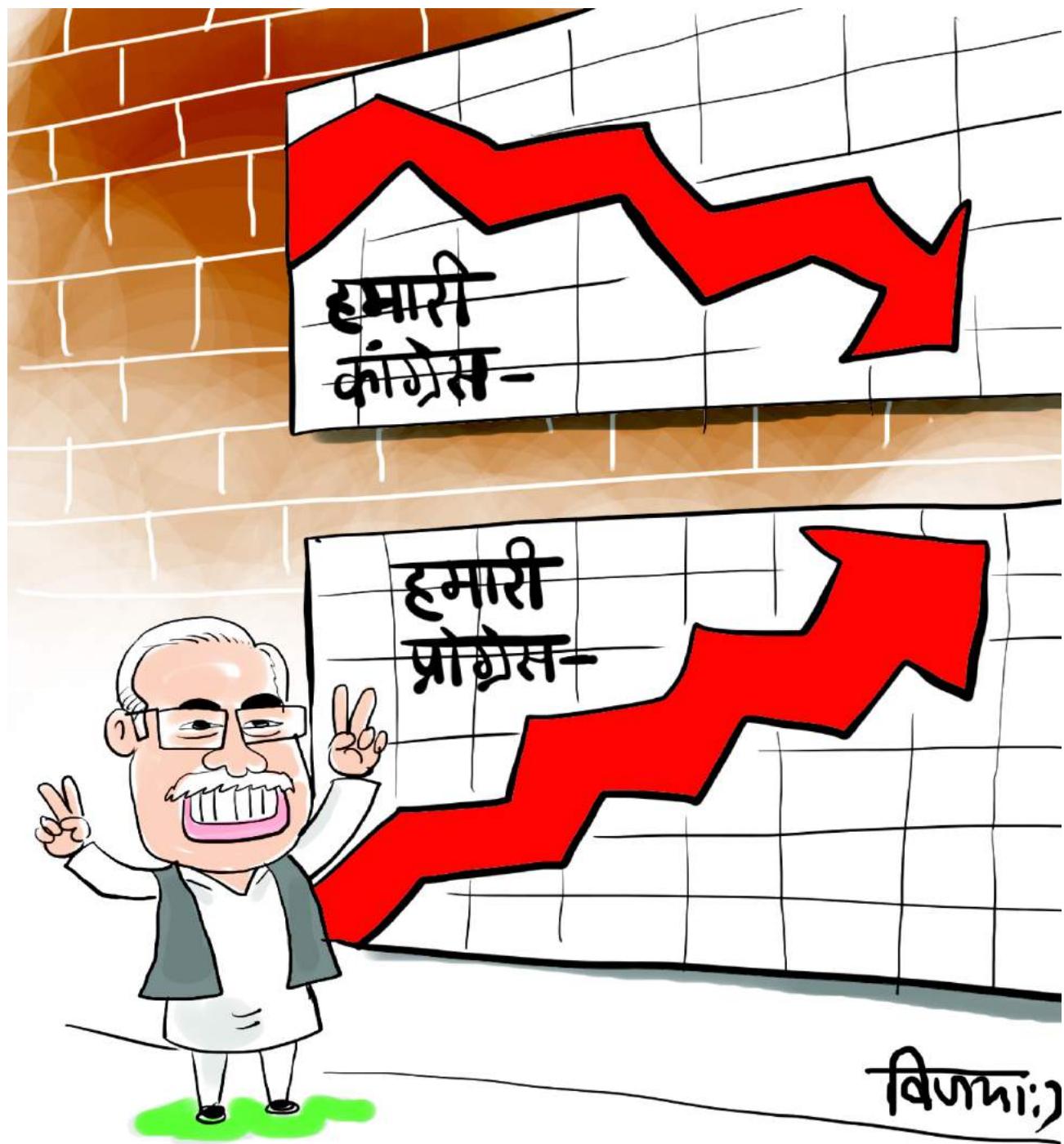
लगभग 41 हजार करोड़ का कर्ज लिया था, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मात्र साढ़े तीन साल के कार्यकाल में लगभग 51 हजार करोड़ का कर्ज ले लिया है। जानकारी के मुताबिक इतने भारी भरकम कर्ज की अदायगी के लिए कांग्रेस सरकार हर माह लगभग 4 सौ करोड़ का भुगतान कर रही है। बताया जाता है कि भारी भरकम भ्रष्टाचार के चलते कांग्रेस सरकार की कोई भी योजना अब तक कामयाब नहीं हो पायी है। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस सरकार के मौजूदा कार्यकाल को खत्म होने में लगभग एक साल बचा है। जबकि मात्र साढ़े तीन साल के कार्यकाल में यह राज्य लगभग 84 हजार करोड़ के कर्ज ढूँढ़ गया है। यह रकम राज्य के कुल बजट की 87 प्रतिशत है। जाहिर है इन बचे हुए महीनों में कर्ज का आंकड़ा अत्यधिक बढ़ जायेगा। चुनावी वर्ष शुरू होते ही नया कर्ज लेने की कवायद में सरकार जोरशोर से जुट जायेगी। ऐसे में कर्ज का आंकड़ा चिंताजनक हालत में पहुंचना लाजिमी है। ऐसे में कर्ज का वित्तीय भार प्रदेश की उस जनता की कंधों पर आयेगा। जिससे कांग्रेस को बड़े अरमानों के साथ सत्ता की चाबी सौंपी थी। लोगों को यह बात अब समझ में आने लगी है कि बघेल सरकार कर्ज लेकर विकास कार्य के बजाय भ्रष्टाचार और अपनों को उपकृत करने में जुटी है। राज्य में आयकर और ईडी की टीम जिस तरह से छापेमारी कर करोड़ों की नगदी और सेल कंपनियों में किए गए निवेश के दस्तावेजों को जब्त कर रही है। उससे साफ़ है कि बघेल सरकार का हाथ भ्रष्टाचार के रंग में रंगा हुआ है।

हकों को ही छीना जा रहा है। राज्य की बेशकीमती धरोहरों को नष्ट किया जा रहा है।

राज्य में सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। प्रदेश की भूपेश सरकार को युवाओं

की कोई चिंता नहीं है। अपने ही किए वायदे से मुकर गई। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात तत्काल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सरकार नौकरी एवं बेरोजगारों को

2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जो आज तक नहीं दिया। 2018 के अंत से प्रारंभ सरकार के कारनामे अब उजागर होने लगे हैं। 04 वर्ष सत्ता सुख भोगने के पश्चात अब इनके कई कांड जनता के



सामने हैं।

छत्तीसगढ़ में मौजूदा कांग्रेस सरकार अपनी अंतिम सांसे गिन रही है। राज्य में

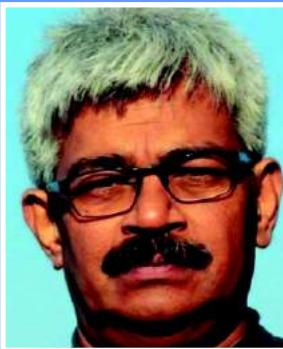
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता का नामोनिशान मिटने के आसार बन गये हैं। दरअसल यह राज्य

कांग्रेस के लिये वरदान साबित हुआ था। उसमें 15 सालों तक सत्ता में वापिस बीजेपी की योजनाओं की विफलताओं को

क्या भूपेश सरकार को चला रही चंडाल चौकड़ी?



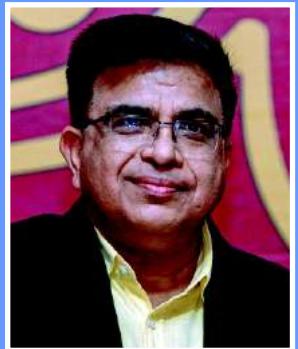
सौम्या चौरसिया



विनोद वर्मा



रुचिर गर्ग



अनिल दुटेजा

आज छत्तीसगढ़ में जो भूपेश और उनकी चौकड़ी ने हाहाकार मचाया हुआ है। भूपेश बघेल की सरकार को 04 लोग मिलकर चला रहे हैं। यह चंडाल चौकड़ी आज पूरे प्रदेश में कुख्यात है। इस चौकड़ी में 02 पत्रकार विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग, एक प्रमोटी आईएएस अफसर अनिल दुटेजा, जो कि नान घोटाले का मुख्य आरोपी है (इनकी भी अपनी टीम है जिसमें एक महापौर एजाज ढेबर और उनके भाई हैं), लाईजनर सर्यकांत तिवारी और मुख्यमंत्री की प्रियतम उप-सचिव सौम्या चौरसिया है। यह पूरी चौकड़ी मिलकर सरकार के हर एक फैसले में दखल अंदाजी करते हैं। वह चाहे किसी भी स्तर का भ्रष्टाचार में रहते हुए भाजपा के मंत्री राजेश मृणत की नकली अश्लील वीडियो बनाकर बंटवाया था। उस समय यह सीडी कांड काफी चर्चित हुआ था। बाद में यह सीडी नकली भी पायी गई थी। विनोद वर्मा भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं। इसके अलावा पत्रकार विनोद वर्मा का लड़का भी जनसंपर्क विभाग से विज्ञापन का काम करता है और प्रदेश की भोलीभालि जनता का पैसा लुटवाता है। इसके बाद बात करते हैं रुचिर गर्ग की। रुचिर गर्ग वर्तमान में मुख्यमंत्री के भीड़िया सलाहकार हैं और मुख्यमंत्री को हर एक विषय पर गलत सलग सलाह देकर सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री की छबि को धूमिल करने पर उतारूँ हैं। रुचिर गर्ग जनसंपर्क विभाग में अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। किसको विज्ञापन देना है, किसको नहीं देना है, यह सब उनके हाथ में है। अब नाम आता है अनिल दुटेजा का, जो नान घोटाले का प्रमुख आरोपी है, जिसे भूपेश बघेल ने सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी है। जब भूपेश बघेल विपक्ष में हुआ करते थे तब नान घोटाले को लेकर काफी हल्ला मचाते थे और इस घोटाले के आरोपियों को जेल में डालने के लिए सरकार पर दबाव बनाते थे लेकिन आज इसके आरोपी भूपेश बघेल के खास बने बैठे हैं। इस चंडाल चौकड़ी में सबसे प्रमुख नाम आता है सौम्या चौरसिया का। कहने को तो यह महिला अधिकारी सीएम हाउस में एक उपसचिव टैक की अधिकारी है लेकिन वर्तमान में यह सरकार में सुपर सीएम के नाम जानी जा रही है। मुख्यमंत्री के बेहद करीब होने का पूरा फायदा सौम्या चौरसिया उठा रही है। यह वही सौम्या चौरसिया है जिस पर अभी-अभी आयकर का छापा पड़ा है। प्रदेश के किसी भी स्तर का अधिकारी हो चाहे पुलिस मुखिया हो या प्रशासनिक मुखिया, जिले का कलेक्टर हो या एसपी सब मैडम की आज्ञा के बिना किसी मंत्री, संतरी या विधायक का काम नहीं करते हैं।

जनता के सामने ऐसा पेश किया था जैसे कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल नहीं बर्लिक

भ्रष्टाचार की फसलें लहलहा रही हैं।

अब राज्य की जनता को लगाने लगा

कि मौजूदा कांग्रेस सरकार उनके गले की फांस बन गई है। पार्टी ने जो बड़े-बड़े वादे



चंडाल चौकड़ी के सामने बेबस, लाचार भूपेश बघेल

किए थे उसकी हकीकत अदालती कार्यवाही में लोगों के सामने है। जनता को

समझ आने लगा कि बीजेपी और उनकी सरकार में प्रभावशील तमाम नेताओं और

अफसरों के खिलाफ झूठा प्रचार कर कांग्रेस ने सत्ता हथिया ली थी। राज्य में

मीडिया पर अंकुश, तानाशाह बने भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार इन दिनों प्रदेश की जनता की सुरक्षा को छोड़ पत्रकारों के पीछे हाथ पोकर पीछे पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री बघेल इन दिनों पूरी तरह हिटलर के स्वरूप में आ खड़े हुए हैं। सरकार की तानाशाही से पत्रकारों में दहशत और भय का माहौल है। सरकार के खिलाफ लिखने पर मीडिया संस्थाओं पर दबाव बना कर नौकरी से निकालने, सोशल मीडिया के पोस्ट हटाने, विज्ञापन रोकने की कार्रवाई आम बात हो गई है। पत्रकारों को धमकाने, पत्रकारों के साथ कांग्रेसियों द्वारा मारपीट करने और पत्रकारों को गिरफ्तार करने के एक के बाद एक मामले बताते हैं कि राज्य में निष्पक्ष पत्रकारिता की जगह कम होती जा रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को भी अब यह सरकार अपने इशारों पर चलाना चाहती है। बघेल के इशारों पर ही पिछले दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस ने आजतक के पूर्व संवाददाता व वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव व उनके साथियों को एक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार किया था। यह सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह से पेश आ रही है तो जनता की क्या मजाल कि वो इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए। भूपेश बघेल मीडिया को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पत्रकार उनके काले करतूतों को बिल्कुल न दिखाए और न ही छापे। बल्कि उनकी साफ और स्वच्छ छवि रोज अखबारों और चैनलों में प्रसारित करें। यह पहला वाक्या नहीं है जब बघेल सरकार ने पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। इससे पहले भी कमल शुक्ला सहित न जाने कितने पत्रकार बघेल की इस निर्दियता का शिकार हुए हैं। लगातार पत्रकारों पर होते एक के बाद एक हमलों के बाद पत्रकारों में दहशत का माहौल है। मैंने भी सरकार की असलियत को खूब उजागर किया है। मुझे भी समय समय पर काफी धमकियां मिली।



छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार नीलेश शर्मा को राज्य की भूपेश सरकार के खिलाफ व्यंग्य लिखने के आरोप में जेल भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि नीलेश शर्मा को 110 किलोमीटर दूर बिलासपुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने का वादा करने वाले, पत्रकारों को ही निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें नीलेश शर्मा पिछले कुछ सालों से खबरों की एक वेबसाइट चलाते हैं। भाजपा शासनकाल में भी उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाले व्यंग्य लेख चर्चा में रहे हैं। आरोप है कि ताज़ा व्यंग्य लेख में उनके वेब पोर्टल पर राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए, ढाई-ढाई साल के फँूर्मूले पर अमल करते हुए सत्ता परिवर्तन की बात कही गई थी। हालांकि, इस व्यंग्य लेख में राज्य सरकार के किसी के भी व्यक्ति के नाम का सीधे-सीधे उल्लेख नहीं था। बल्कि उन नामों की जगह दूसरे नाम लिखे गए थे।

पत्रकार सुरक्षा कानून- विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल पत्रकारिता की स्वतंत्रता के पक्षधरों में शुमार होते रहे थे। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विधानसभा में निजी विधेयक प्रस्तुत करने की भी बात कही थी। हालांकि यह विधेयक कभी पेश नहीं किया गया। विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी वकीलों, चिकित्सकों और पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद इन कानूनों को सरकार ने खूब प्रचारित किया लेकिन अब जबकि राज्य में फिर से विधानसभा चुनाव की प्रयिता में महज 18 महीने बचे हैं, इन कानूनों का कहीं अता-पता नहीं है। हालत ये है कि राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू किए गए आंदोलन के संयोजक, बस्तर के पत्रकार कमल शुक्ला और सतीश यादव की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में, कांग्रेस नेताओं पर थाने के भीतर ही मारपीट का आरोप है।

भूपेश बघेल और उनके साथियों ने मुख्यमंत्री के पद और सरकार के अधिकारों

का जिस तरह से दुरुपयोग किया है, उससे साबित होता है कि लूटमार की प्रवृत्ति से ही

उनका भला होने वाला है, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और जनहित के



कार्यों से नहीं।

प्रदेश के पत्रकारों पर जिस तरह से

शिकंजा कंसा गया है और कई नामचीन पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कर

उन्हें महिनों तक जेलों में निरुद्ध रखा गया। उससे पत्रकारिता की दशा और दिशा ही

पत्रकारों पर भूपेश बघेल का सख्त पहरा

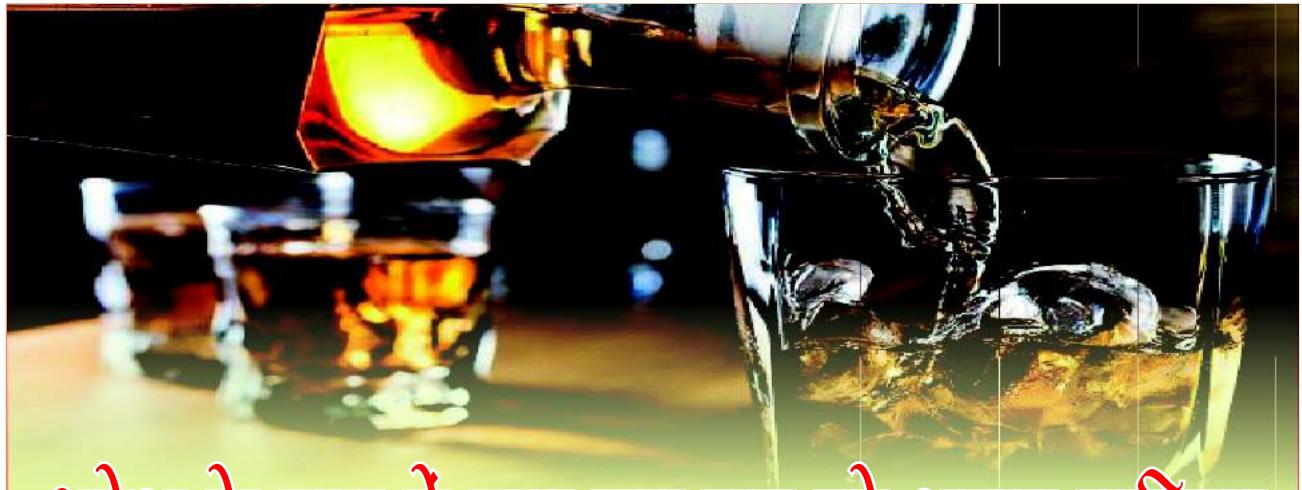
सब दबाने के लिए पत्रकार सुनील नानदेव को हिरासत में पिलाया सेनेटाइजर



बदल गई। इन 04 सालों में अब वही पत्रकार शेष बचे हैं जो राज्य की कांग्रेस

सरकार का गुणगान करने में माहिर माने जाते हैं। हकीकत बयां करने वाले पत्रकारों

को ठिकाने लगाने की योजना कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों में से एक है। आम जनता



भूपेश के राज में खूब फल फूल रहे शराब माफिया

छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों में पहले से रेत माफिया, कोयला माफिया, कृषि में सप्लाई माफिया, नशा माफिया, ठग माफिया, फिरौती माफिया में राज्यों से शराब की तस्करी कर छत्तीसगढ़ में परोसने का कीर्तिमान भी शामिल हो गया है। इसके लिए शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस को प्रदेश की जनता को शराबी प्रदेश बना रही है। छत्तीसगढ़ में नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स, कोकिन, और ना जाने कैसे कैसे सूखे नशे जिनका नाम तक छत्तीसगढ़ के वासियों ने कभी नहीं सुना था का काला नशीला धुंआ छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रहा है। भूपेश बघेल सरकार विफल होने के साथ-साथ अराजकता की स्थिति निर्मित कर चुकी है। हत्या, लूट, डैकैती, अपहरण जैसी वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान उड़ा छत्तीसगढ़ बनने की ओर अग्रसर हो रही है। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ में लगातार शराब की तस्करी हो रही है। गंगाजल हाथ में लेकर प्रदेश की जनता व माताओं एवं बहनों से शराबबंदी का वादा करने वालों के राज में धड़ल्ले से शराब परोसने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में भूपेश बघेल के राज में शराब परोसे जाने का हर एक विकल्प आज उपलब्ध है, शराब की होम डिलवरी की बात करें, शराब दुकानों में अवैध शराब की ब्रिकी की बात करें, प्रदेश भर में शराब कोचियों को संरक्षण देने या बढ़ावा देने की बात करें या फिर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों से खुलेआम शराब की तस्करी की बात करें छत्तीसगढ़ शराब उपलब्ध कराने के हर विकल्प को खुली छूट देकर नंबर वन बन गया है। अन्य राज्यों से शराब की तस्करी और छत्तीसगढ़ में शराब खपाने का खेल बिना मिली भगत या संरक्षण के कैसे संभव हैं।

के सिर से मुख्यमंत्री बघेल और कांग्रेस का भूत तेजी से उत्तर रहा है। वर्ही लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस से तो बेहतर पुरानी बीजेपी सरकार ही थी। यही नहीं कांग्रेस की जड़ों पर जिस तरह से मुख्यमंत्री बघेल और उनके करीबियों ने हमला किया है उससे आम कांग्रेसी थी सदमे में हैं। उन्हें भी आभास होने लगा है कि पार्टी के प्रबुद्ध वाले इलाकों में अभी से उनके पैर उखड़ने

लगे हैं। जनता के साथ वादाखिलाफी और भय, आंतक, साथ लूटमार वाली छबि बनने से कांग्रेस के हाथों से सत्ता से छूट जाने का भय जमीन से जुड़े नेताओं के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है।

एक दौर था जब संयुक्त मध्यप्रदेश में सत्ता की चाबी छत्तीसगढ़ के नेताओं के हाथों में होती थी। यहां से कांग्रेस के विधायक थोक के भाव जीतकर आते थे

लेकिन 2003 में कांग्रेस अपनी कार्यप्रणाली के चलते मतदाताओं की नजरों से गिर गई थी। नतीजतन इस प्रदेश में बीजेपी का परचम लहराया। बीजेपी ने पूरे 15 सालों तक अपनी सरकार कायम रखी। कट्टर कांग्रेसियों की मेहतन रंग लायी और 2018 के जिस चुनाव में बीजेपी का सूर्योस्त हो गया। कांग्रेस ने उसका सूपड़ा-साफ कर भारी मतों से कांग्रेस की सरकार

दावते इस्लामी संगठन को रायपुर में बसाने की थी तैयारी

छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर में रोहिंग्याओं की नजर है। सत्ता के संरक्षण में भू-माफिया मैदान में उतर आए हैं। एनआरडीए और टाउन कंट्री प्लानिंग के अफसरों की संदिग्ध गतिविधियाँ चर्चा में हैं। नया रायपुर के नाम पर जमीन का जो खेल रचा जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। नवा रायपुर अटल नगर के हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस इलाके में आम लोग हों या किसान, उनकी जमीनों पर सत्ताधारी दल के मंत्री मो. अकबर के भाई असगर का कब्जा होता जा रहा है। असगर और उसके कुनबे ने पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा दिया है। उनके प्रभाव में एनआरडीए और टाउन कंट्री



प्लानिंग के अफसर किसी निजी मुलाजिम की तरह लोगों के घरों में दबिश दे रहे हैं। नई राजधानी के ज्यादातर इलाकों में निवासित लोगों पर बगैर अनुमति निर्माण का आरोप लगाकर उनके घरों को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। अन्यथा जमीनों को असगर को सौंपे जाने का दबाव डाला जा रहा है। इसके लिए एनआरडीए के साथ-साथ टाउन कंट्री प्लानिंग के अफसर कानूनी दांव पेंचों का सहारा लेकर नागरिकों पर भारी दबाव दाल रहे हैं। नई राजधानी के लेयर-2 और लेयर-3 के कई घरों में इस तरह के नोटिस को लेकर तनाव का माहौल है। गौरतलब है कि एनआरडीए के गठन में इस तरह की किसी भी कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है। ग्राम पंचायत का इलाका होने के चलते टाउन कंट्री प्लानिंग के प्रावधान भी यहाँ विधि संगत रूप से लागू नहीं होते। लेकिन असगर के प्रभाव और उसके गैरकानूनी सलाहकारों के इशारे पर यहाँ कानूनी दांवपेंचों का खेल जोरों पर है। सूत्र बताते हैं कि रायपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोहिंग्याओं को बसाने के लिए सुनियोजित योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में खटीदी जा रही जमीनों पर रोहिंग्याओं को बसाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। खासतौर पर नवा रायपुर हज हॉउस के चारों ओर स्थित गांव में बाहरी लोगों की आवाजाही और उनकी संदिग्ध गतिविधियों को इस योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। अकेले रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 700 एकड़ से ज्यादा की बेशकीमती जमीनों पर असगर और उसके कुनबे का नामी बेनामी कब्जा है। पिछले तीन सालों में फारेस्ट, हाऊसिंग बोर्ड, आवास और पर्यावरण समेत कई और सरकारी विभागों में ठेकेदारी और अन्य गतिविधियों से टीम अजगर रोजाना करोड़ों की काली कमाई अर्जित कर रहा है। दावते इस्लामी जैसे कई संगठन अजगर की सरपरस्ती में प्रदेश में अपनी जड़ें जमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर में दावते इस्लामी नाम के संगठन को 25 एकड़ (10 हेक्टेयर) जगह आवंटित कर रही थी। दावते इस्लामी एक पाकिस्तानी संगठन है, जिसकी शाखाएं हमारे देश में खोलने का काम भूपेश सरकार कर रही थी। हाल ही में उदयपुर में इसी संस्था के गुर्गे हैं जिन्होंने कब्जैयालाल की हत्या की थी। दावते इस्लामी के ऊपर मतांतरण और आतंकवाद फैलाने व चंदे के जरिए फंडिंग के आरोप लग चुके हैं और इस संगठन से जुड़े आतंकवादियों जासूसों को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा है। छत्तीसगढ़ के दावते इस्लामी संगठन ने अपने फेसबुक पेज पर पाकिस्तानी संस्थापक इलियास कादरी की फोटो भी पोस्ट की है। पाकिस्तानी संगठन और छत्तीसगढ़ दावते इस्लामी संगठन का चिन्ह (मोनो) भी एक ही है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे पाकिस्तानी संगठन को 10 लाख 76 हजार स्क्वायर फीट जगह सामुदायिक भवन के लिए दान कर रही थी। क्या इतिहास में किसी भी समाज को सामुदायिक भवन बनाने के लिए इतनी बड़ी जगह आवंटित की गई है? क्या सामुदायिक भवन बनाने के लिए 25 एकड़ जगह लगती है? ऐसे पाकिस्तानी संगठन को इतनी बड़ी जगह क्या आकाओं के आदेश पर आवंटित की जा रही थी? सरकार अपना स्पष्टीकरण दें।

को सत्ता के शीर्ष पर बैठाया। लेकिन वही कद्दर कांग्रेसी अब मान रहे हैं कि मौजूदा

कांग्रेस के मुखिया ने पार्टी की नेया ढुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी यह भी

दलील है कि बीजेपी की विफलताओं को लेकर प्रदेश का माहौल बदलने में उनकी

भूपेश सरकार को जमीन देने की जरूरत क्यों पड़ी?



आखिर भूपेश सरकार को दावत-ए-इस्लामी संगठन को 25 एकड़ जमीन देने की क्या जरूरत पड़ी? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में भी कई ऐसे संगठन हैं, जो देश के विकास में, समाज के कल्याण में अपना योगदान देना चाहते हैं। क्या ऐसे समाजसेवी संगठनों

को जमीन क्यों नहीं देना चाहिए। पाकिस्तानी संगठनों को जमीन आवंटित कर क्या भूपेश सरकार प्रदेश में आतंकवाद को पनपने का अवसर देना चाहते थे। ऐसे गंभीर मामले पर केन्द्र सरकार या जाँच एजेंसियों को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा जरूर ही खतरे में होती। शुक्र हैं तमाम दबावों के बाद भूपेश बघेल को झुकना पड़ा। नहीं तो सरकार ने तो जमीन आवंटित करने का पूरा फैसला कर लिया था।

मुख्य भूमिका रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी शासनकाल के हिसाब-किताब को जनता के सामने लाया जायेगा लेकिन इन 04 वर्षों में कांग्रेस के कर्णधार सरकारी संरक्षण में अपना ही हिसाब-किताब करने में व्यस्त रहे। यह हिसाब-किताब इतने ऊँचे स्तर का था कि आयकर और ईडी की टीमों को छत्तीसगढ़ का रुख बार-बार करना पड़ा। भला हो कांग्रेस नीति का। उसने

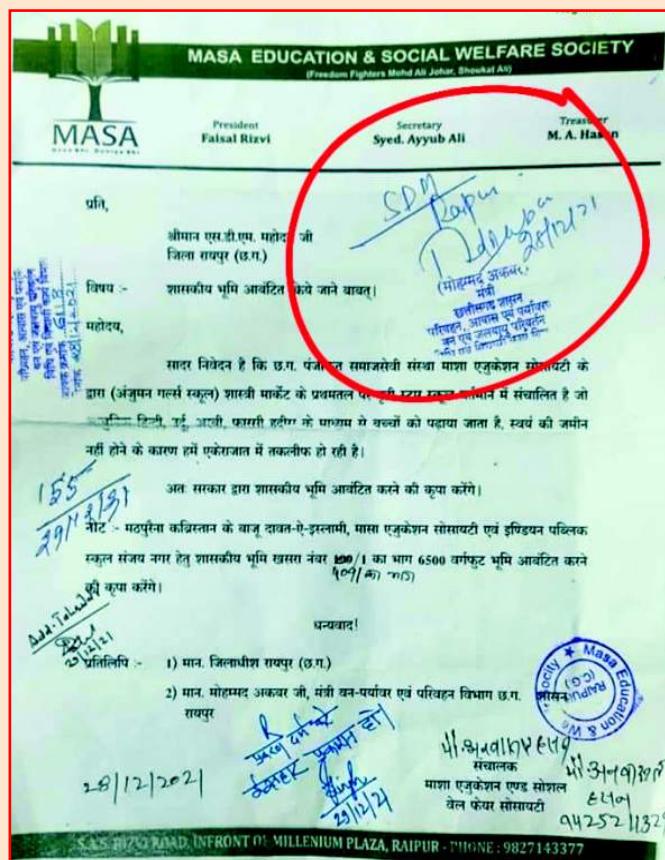
अपने शासित प्रदेशों में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी। वरना कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण नेताओं के दरवाजे पर सीबीआई की टीम भी डटी नजर आती। कुल मिलाकर इन 04 सालों में कांग्रेस की सरकार ने अपनी करनी से बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों की नींव मजबूत करने के अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री बघेल नीतियों और कार्य प्रणालियों से साफ नजर

आने लगा है कि शहरी इलाकों के बाद अब ग्रामीण अंचलों में भी कांग्रेस का प्रभाव तेजी से खत्म हो रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो पंजाब की तर्ज पर छग में कांग्रेस का सफाया होना तय है।

आज छत्तीसगढ़ अपनी बदहाली पर रो रहा है। आदिवासी वहीं पर खड़ा है। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया।

**दबाव में भूपेश सरकार ने पाकिस्तानी
संगठन को दी जा रही 25 एकड़ जमीन
की अनुमति रद्द की**

छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर में दावते इस्लामी नाम के संगठन को 25 एकड़ (10 हैक्टेयर) जगह आवंटित कर रही थी। जिसे काफी दबाव के बाद रद्द कर दिया गया है। दावते इस्लामी एक पाकिस्तानी संगठन है, जिसकी शाखाएं हमारे देश में खोलने का काम यह कांग्रेसी कर रहे थे। दावते इस्लामी के ऊपर मतांतरण और आतंकवाद फैलाने व चंदे के जरिए फंडिंग के आरोप लग चुके हैं और इस संगठन से जुड़े आतंकवादियों, जासूसों को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा था। छत्तीसगढ़ के दावते इस्लामी संगठन ने अपने फेसबुक पेज पर पाकिस्तानी संस्थापक इलियास कादरी की फोटो भी पोस्ट की है। पाकिस्तानी संगठन और छत्तीसगढ़ दावते इस्लामी संगठन का चिन्ह भी एक ही है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे पाकिस्तानी संगठन को 10 लाख 76 हजार स्क्वायर फीट जगह सामुदायिक भवन के लिए दान कर रही थी। क्या इतिहास में किसी भी समाज को सामुदायिक भवन बनाने के लिए इतनी बड़ी जगह आवंटित की गई है? क्या सामुदायिक भवन बनाने के लिए 25 एकड़ जगह लगती है? ऐसे पाकिस्तानी संगठन को इतनी बड़ी जगह आकाओं के आदेश पर आवंटित करने के पीछे भूपेश सरकार की क्या मंशा थी?



मो. अकबर का यह वही पत्र है जिसमें जमीन आवंटित करने की मांग की गई थी।

आदिवासी सहित सभी वर्गों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान इतने वादे किए थे युवाओं से, बेरोजगारों से, अनियमित कर्मचारियों

से, पुलिस के जवानों से, किसानों से, गरीबों से, महिलाओं से, सब धरे के धरे रह गए हैं। आज छत्तीसगढ़ सरकार की कारगजारियों का प्रत्यक्ष गवाह बन चका

है। इस सरकार को एक पल भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। काँग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल निर्मित कर दिया है। हर तरफ रेत

[← Tweet](#)



Brijmohan Agrawal @brijmohan_ag

भूपेश बघेल जिस पाकिस्तानी संस्था दावते
इस्लामी को छ.ग. में 25 एकड़ जमीन अलॉट कर
रहे थे, हमारे विरोध करने पर जिसका अलॉटमेंट
रद्द किया गया था, #उदयपुर में #कहैयालाल की
हत्या करने वाले दोनों व्यक्ति भी इस पाकिस्तानी
संस्था से जुड़े थे। काँग्रेस की देश विरोधी मंशा
समझ से परे है।

[Translate Tweet](#)



[Tweet your reply](#)



नवा रायपुर क्षेत्र में स्थित यही जमीन है जिसे प्रदेश की
मौजूदा भूपेश सरकार ने आतंकवादी संगठन दावत-ए-
इस्लामी को आवंटित किया था। हालांकि तमाम दबाव के
कारण भूपेश सरकार ने इस जमीन का आवंटन भूपेश
सरकार को रद्द करना पड़ा। यहां सवाल उठता है कि आखिर
वह कौन सी वजह थी जिसके कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
एक आतंकवादी संगठन को 25 एकड़ जमीन आवंटित
करने जा रहे थे।

माफिया, कोयला माफिया, शराब माफिया,
ट्रांसफर माफिया, चोर डॉकेत, लुटेरे,
बलाकारी ऐसे अराजक लोगों को सिर्फ
छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बढ़ावा दिया
है। आने वाले समय में जनता हर कृत्य का
हिसाब लेगी। उसी प्रकार ऑर्गेनिक खेती
करवाने के नाम पर किसानों से 02 रुपए
प्रति किलो में गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट
के नाम पर उसी गोबर को 10 रुपए प्रति
किलो किसानों को जबरन बेचा जा रहा है।
प्रदेश में अधिकतर गौठान जर्जर हालत में
हैं एवं चारा के अभाव में गोवंश मारे जा रहे
हैं। खेती के लिए किसानों की विजली में

**काँग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में
अराजकता का माहौल निर्मित
कर दिया है। हर तरफ रेत
माफिया, कोयला माफिया,
शराब माफिया, ट्रांसफर
माफिया, चोर डॉकेत, लुटेरे,
बलाकारी ऐसे अराजक लोगों को
सिर्फ छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार
ने बढ़ावा दिया है। आने वाले
समय में जनता हर कृत्य का
हिसाब लेगी।**

कटौती की जा रही है। सरकार किसानों को
समय से खाद और पानी नहीं दे पा रही है।

**गरीबों के स्कूल पर भूपेश बघेल ने
डाला डाका-** भिलाई में एक सरकारी
स्कूल था, जिसे नगरपालिका संचालित
करता था। बाद में यह स्कूल साडा के अंदर
आ गया। इस जमीन को भूपेश बघेल के
मालगुजार दादाजी ने गरीब विद्यार्थियों की
शिक्षा के लिए दान में दे दिया था। इस गरीब
बच्चों की शिक्षा के लिए बना जनता उच्च
माध्यमिक विद्यालय को लेकर तब
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत बड़ा बड़यत्र
रचा। भूपेश बघेल ने अपने दादाजी को

रणनीति बनाने में असफल बघेल

उत्तरप्रदेश में करारी हार के जिम्मेदार भूपेश बघेल

हरियाणा में 02 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव थे। कयास लगाए जा रहे थे कि एक सीट पर भाजपा तो दूसरी पर कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां बड़ा उलटफेर कर दिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन चुनाव में हार गए। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। हरियाणा की लगभग जीती हुई राज्यसभा सीट पर बघेल की अकुशलता, अहंकार और अति आत्मविश्वास से हार गई। बता दें कि क्रॉस वोटिंग के डर से हरियाणा के 28 विधायकों को करीब सप्ताह भर तक छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के होटल में रखा गया था। रिसार्ट में पूरी चाक चौबंद और व्हीआईपी व्यवस्था के साथ पूरे एक सप्ताह से रखा गया था। इसका मतलब साफ है कहीं न कहीं नियुक्त पर्यवेक्षक की नेतृत्व क्षमता कमजोर रही, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी जीतने में सफल नहीं हुए।

उत्तरप्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार चुनावी इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। राज्य में खराब प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया गया था। क्योंकि पार्टी ने बघेल को चुनाव का प्रभारी पर्यवेक्षक बनाया था। बघेल ने प्रदेश की कुल 42 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। जिसमें से 41 जगहों पर पार्टी बुरी तरह हारी। वोट प्रतिशत केवल 2,33 पर आ गया। सूत्र बताते हैं कि जिन नेताओं को उत्तरप्रदेश चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया था वे नेता होटल से बाहर ही नहीं निकले। प्रियंका गाँधी स्वयं उत्तरप्रदेश में चुनाव के शुरुआती दौर में ही लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे लेकर चुनाव मैदान में जोश और खरोश के साथ उतरी थीं। साथ ही महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण में कोई कमी नहीं की थी। 44ल ल सीटें महिलाओं को दी थीं। जिस प्रकार प्रियंका गाँधी ने उत्तरप्रदेश में जी तोड़ मेहनत की थी।

मानसिक रूप से विक्षिप्त साबित कर डाला। अपने तरफ से इस जमीन को उन्होंने अपनी आजीविका के लिए वापस मांगा और तब के साड़ा के अयक्ष लक्ष्मण चंद्राकर के साथ मिलकर गरीब बच्चों के शिक्षा के मंदिर जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय को उजाड़ डाला।

नान घोटाले को दबाने की पूरी कोशिश-भूपेश बघेल द्वारा 36,000 करोड़ के नान घोटाले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके मुख्य अभियुक्त प्रदेश चला रहे हैं। प्रवर्तन



ब्राह्मण विरोधी बयानों में बादशाहत

भूपेश बघेल और उनके पिता नंदकुमार बघेल ब्राह्मण विरोधी बयानों के लिए कुख्यात हैं। उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान नंदकुमार बघेल ने ब्राह्मणों के विरोध में कई बयान दिए थे जिनका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। कुछ ऐसी ही सोच भूपेश बघेल की है, जो पिता के कंधे पर बंदूक रखकर बयानों की गोलियां चलाते हैं। बघेल ने संत कालीचरण को एक बयान के मामले में मध्यप्रदेश से गिरफ्तार करवाया था।

(विजयाङ्कुर)



निदेशालय ने तो सुप्रीम में कहा था कि भूपेश बघेल के आदेश पर बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्यों, मुख्यमंत्री, कानून अधिकारी ने इस घोटाले में दो वरिष्ठ आईएएस को बचाने के लिए मामला कमज़ोर कर दिया। यह गरीब का राशन था, जिसे इन भ्रष्टाचारियों ने खा डाला।

छत्तीसगढ़ में जारी है आदिवासियों का शोषण- सत्ता में आने के समय कांग्रेस ने आदिवासियों से उनकी रक्षा, विकास और बड़े औद्योगिक घरानों से उनकी जल, जंगल एवं जमीन को बचाने के वायदे किये थे। उस समय कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने तो आदिवासियों के साथ में अड़ानी को दी जाने

वाले लेमरू खदान के खिलाफ अनशन भी किया था। पर सत्ता मिलते ही भूपेश बघेल ने सबसे पहले प्रदेश के आदिवासियों को लूटा। जिस लेमरू खदान जिसका विरोध राहुल गांधी ने किया था उनकी बात न मानते हुए भी भूपेश बघेल ने यह खदान का संचालन अड़ानी को सौंप दिया।

क्या सीएम भूपेश पर भारी पड़ने लगी है सौम्या चौरसिया?

भरी कैबिनेट में भूपेश बघेल को दिखाया नीचा

छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुई आयकर विभाग के छापेमार कार्यवाही की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि भूपेश बघेल की कैबिनेट में भूचाल आ गया। सूत्रों के हवाले से मालूम हुआ है कि इस बार भूचाल आयकर विभाग की वजह से नहीं बल्कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की करीबी अफसर सौम्या चौरसिया के हस्तक्षेप के बाद आया है। यह वही सौम्या चौरसिया है जिनके ठिकानों पर पिछले दिनों आयकर विभाग ने छापेमार कार्यवाही के बाद वहाँ से करोड़ों रुपये के हेराफेरी और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज एकत्रित किये थे। सूत्रों के मुताबिक सौम्या चौरसिया एक बार तब फिर सुर्खियों में आई जब उन्होंने भूपेश बघेल की कैबिनेट के द्वारा पीछे की कुर्सी से उठकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बगल में कुर्सी लगाई और मुख्यमंत्री को चुप कराकर खुद बोलना शुरू हो गई। सौम्या चौरसिया का यह रूप देख कैबिनेट के भीतर बैठे तमाम मंत्री, अफसर दंग रह गये और सभी एक-दूसरे



के चेहरे की तरफ देख इस पूरे वाक्ये के तमाशाबीन बने रहने पर मजबूर हुए। भूपेश बघेल की कैबिनेट में सौम्या चौरसिया का यह रौद्र

नाखुश प्रदेश के कर्मचारी- ऐसा ही एक मामला भूपेश बघेल की वादाखिलाफी का है। सरकार के 3 साल होने के बाद भी

प्रदेश में एक लाख अस्सी हजार कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया। यह सभी 1.80 लाख कर्मचारी

सरकार के खिलाफ लापबंद हो गए हैं। कुल लब्बोलुवाब यह है कि प्रदेश की खस्ता हालत और भ्रष्टाचार मॉडल से आम



रूप देख कुछ देर तक सभी दंग रह गये। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि भूपेश बघेल बैठे रह गये और पूरी कैबिनेट के दौरान सौम्या चौरसिया ने सभी मंत्रियों की क्लास ले ली। दरअसल कैबिनेट समापन के बाद जब मुख्यमंत्री ने अभी पड़े प्रदेश के आयकर छापों के बारे में बोलना शुरू किया था तो उनको सौम्या चौरसिया ने चुप करा दिया। सूत्रों के मुताबिक पूरी बातों का लब्बोलुबाब यह था कि इस बार के छापों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल बिट्ठु को भी पूछताछ में बुलाया था। सौम्या चौरसिया ने धमकी भरे अंदाज में मंत्रियों को यह हिदायत दी कि पिछले दिनों आयकर की छापेमार कार्यवाही जो मेरे ऊपर हुई है वो किसी के ऊपर भी हो सकती है। अभी तक इसके दायरे में केवल मैं और मुख्यमंत्री के बेटे आए हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप सभी इसके दायरे में होंगे। सौम्या ने कहा कि सभी के लिए यह बेहतर होगा कि आप सब भी हमारे साथ इस कार्यवाही के विरोध में

छत्तीसगढ़िया बहुत परेशान हो चुका है। ऐसी अधोषित इमरजेंसी जैसे हालात से छत्तीसगढ़ को मुक्त होना चाहिए।

पूरे प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से जनता के बीच भय और डर व्याप्त हो चुका है जिसका तात्पर्य जनता का इस सरकार

पर से विश्वास उठ चुका है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते माफियाराज, अवैध शराब, शराब की तस्करी व अपराध में अप्रत्याशित तेजी

सचिव छाता लगाते दिखे थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों की बिल्कुल नहीं चलती। कुछ 2-3 मंत्रियों को छोड़कर किसी को फ्री हैंड नहीं दिया है।

सौम्या चौरसिया के ऊपर भूपेश बघेल की मेहरबानी का एक नहीं कई कारण है। पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि सौम्या चौरसिया बघेल की सबसे करीबी अफसर मानी जाती हैं। उनके कहने पर ही राज्य के अंदर अफसरों के ट्रांसफर, पर्सिंग की सूची तैयार होती है। अफसरों से मिलने वाले करोड़ों रुपये के लेनदेन की मालिकिन भी सौम्या चौरसिया ही है। भूपेश की चौकड़ी ने पूरे प्रदेश को घेरे रखा है ना कोई मंत्री, विधायक या पीसीसी अध्यक्ष किसी की भी उनके आगे नहीं सुनी जाती है। वैसे वास्तविकता तो छत्तीसगढ़ की यही है की जिले का कोई कलेक्टर एसपी, विधायक या मंत्री का काम करने से पहले मैडम से पूछेगा। यह बात वैसे बहुत छोटी दिखती है पर इस समय यह तस्वीर छत्तीसगढ़ की असलियत बायां कर रही है।

अपने इस कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के खजाने को खंडहर कर दिया है। इनकी लूट वाली क्रोनोलॉजी भी समझिए। सरकार बनते ही अपने आसपास सरकार चलाने के लिए पूरी चौकड़ी (चंडाल-चौकड़ी) बनाई। इस चौकड़ी में 02 पत्रकार विनोद वर्मा और रूचिर गर्ग, एक प्रमोटी आईएएस अनिल टुटेजा (जो नान घोटाले का मुख्य अभियुक्त था), उनके खास सिपहसालार के तौर पर महापौर ढेबर और उनके भाई और एक



अपनी प्रियतम राज्य स्तरीय महिला अधिकारी सौम्या चौरसिया। इसके अलावा अब एक नया नाम और जुड़ गया है सूर्यकांत तिवारी का। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पड़े आयकर के छापों में सूर्यकांत तिवारी का नाम सबसे प्रमुखता से छाया है। इस पूरे सिंडिकेट ने हर तरीके से प्रदेश को लूटना चालू किया। अवैध कोल टैक्स, शराब टैक्स, ट्रांसफर, जनसंपर्क (दोनों पत्रकार सलाहकारों को फ्री हैंड), कृषि, हर विभाग से प्रदेश को लूटना चालू कर दिया। छत्तीसगढ़ की यह ऐसी ऐतिहासिक लूट रही जिसके आंकड़े 01 लाख करोड़ से ऊपर निकल गये। इसी के साथ भूपेश बघेल देश के सबसे धनाढ़ी कांग्रेसी बन गए। छत्तीसगढ़ की इस महा लूट पर पर्दा डालने के लिए दिल्ली मीडिया के माध्यम से अपने आप को लायक साबित करने की कोशिश चलती रही। जब प्रदेश की ढाई-ढाई साल वाली आग 10 जनपद पहुंची तो विधायकों को दिल्ली परेड करा दी और वहां ऐश-ओ-आराम में कोई कमी नहीं होने दी। इन सबका अरेजमेट अभी के आयकर छापों वाले सूर्यकांत तिवारी ने की, जो कि भूपेश की प्रियतम और आज की सुपर सीएम सौम्या चौरसिया के निर्देश पर काम करते रहे। वहीं उसी समय

निश्चित ही चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में इस समय सिर्फ भ्रष्टाचार, दमन, अत्याचार का राज है और भूपेश बघेल

किसी राजा के माफिक राज्य चला रहे हैं। भ्रष्टाचार और अव्याशी में ढूबे मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर सभी आवाज को दबाकर रख

दिया है। यह कांग्रेस आलाकमान को समझना होगा अन्यथा आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता इस भ्रष्ट, विनाशी

इनमें से कुछ 15-16 विधायकों की ऐश-ओ-आराम की सीड़ी बना ली गई, जो इस आयकर के छापों में अब केंद्र के हाथ लग गए हैं। बाकी बचे कुछ अति महत्वपूर्ण अधिकारीयों की भी काली करतूतें इन सीड़ी में हैं। इन विधायकों इसके द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था ताकि वो भूपेश का पाला ना छोड़े। सूत्रों की माने तो इस मामले की भी जांच हो सकती है। निश्चित ही इन सब का डायरेक्शन भूपेश बघेल ने ही किया होगा। पूर्व में भी राजेश मूंदत की अश्लील सीड़ी कांड में भूपेश और विनोद वर्मा (पत्रकार) मुख्य आरोपी हैं, इनको ऐसे कामों का एक्सपरीरिंग भी है। आयकर विभाग की विज्ञप्ति में भी साफ-साफ डिजिटल एविडेंस और कोयले वाले 200 करोड़ का की बात कही गई है। 4-5 दिन चले आयकर के छापों में सौम्या चौरसिया के साथ सूर्यकांत तिवारी एंड ग्रुप के पूरे तार पकड़े गए हैं। वैसे तो अभी कुल लूट का आयकर विभाग ने 1-2 प्रतिशत ही पकड़ा है, पर सूत्रों के मुताबिक आगे ईडी का रोल भी आने वाला है।



मुख्यमंत्री और इनकी सरकार को सबक सिखाएगी।

भूपेश सरकार ने अपने शासन में

छत्तीसगढ़ मॉडल का कांसेप्ट लेकर आए। इस में सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़-बड़े सपने दिखाए हैं। लेकिन इसकी सच्चाई

आज सबके सामने है। छत्तीसगढ़ मॉडल के कू-मॉडल के खिलाफ कोई लिखता है या आवाज उठाता है तो उसे पुलिस महकमे

रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, सूरजपुर आदि में फैले 30 से अधिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, कागजात और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। समूह द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली में छत्तीसगढ़ राज्य भर में कोयला परिवहन पर नियमित रूप से अनुचित कलेकशन शामिल है, जिससे भारी मात्रा में बेहिसाब आय अर्जित की गई है। कम समय में इस तरह से अर्जित 200 करोड़ से ज्यादा रुपये के संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं। समूह के प्रमुख विश्वसनीय सहयोगियों ने भी इसकी पुष्टि की है। सरकारी अधिकारियों को किए गए कुछ नकद भुगतान के उदाहरणों की भी पहचान की गई है। जब्त किए गए सबूतों से यह भी संकेत मिलता है कि समूह ने कोल वाशरीज की खरीद में लगभग 45 करोड़ रुपये का बेहिसाब नकद भुगतान किया है। इसके अलावा हाल ही में हुए चुनावों के दौरान समूह द्वारा नकद खर्च करने के सबूत भी मिले हैं। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में संपत्ति के समझौते मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में भारी अघोषित निवेश किया गया है, जो कि प्रकृति में बेनामी प्रतीत होते हैं। सरकारी अधिकारी से संबंधित कथित मालिकों द्वारा 50 एकड़ अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में किए गए निवेश के स्रोत की जांच की जा रही है। तलाशी अभियान के दौरान अब तक 9.5 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकदी और 4.5 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए जा चुके हैं। तलाशी के दौरान एकत्र किए गए ऐसे आपत्तिजनक सबूतों की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि समूह द्वारा कुछ सौ करोड़ रुपये की आय से बचने का प्रयास किया है। आगे की जांच जारी है।

जांच का दायरा बढ़ने और विभिन्न जांच एजेंसियों के शामिल होने के संकेत- आयकर विभाग ने संकेतों में सही पर यह स्पष्ट कर दिया है कि, कोयले के परिवहन को लेकर जो 25 रुपए टन की अवैध वसूली हो रही थी, और कोरबा की वह ज़मीन जिसमें कोल वाशरी को लेकर ख़रीदी का मसला बताते हुए संकेत दिया था कि, यह दो मसले ऐसे थे जिससे आयकर और दिगर केंद्रीय एजेंसियों टीम के राडार पर सूर्यकांत आ गए थे। आयकर विभाग ने डिजिटल साक्ष्य शब्द का प्रयोग किया है, इसके अर्थ सामान्य तौर पर सीड़ी या पैन ड्राइव से लगाए जाते हैं। आयकर विभाग ने विज्ञाप्ति में हाल के चुनाव का ज़िक्र किया है, इसे हालिया उप



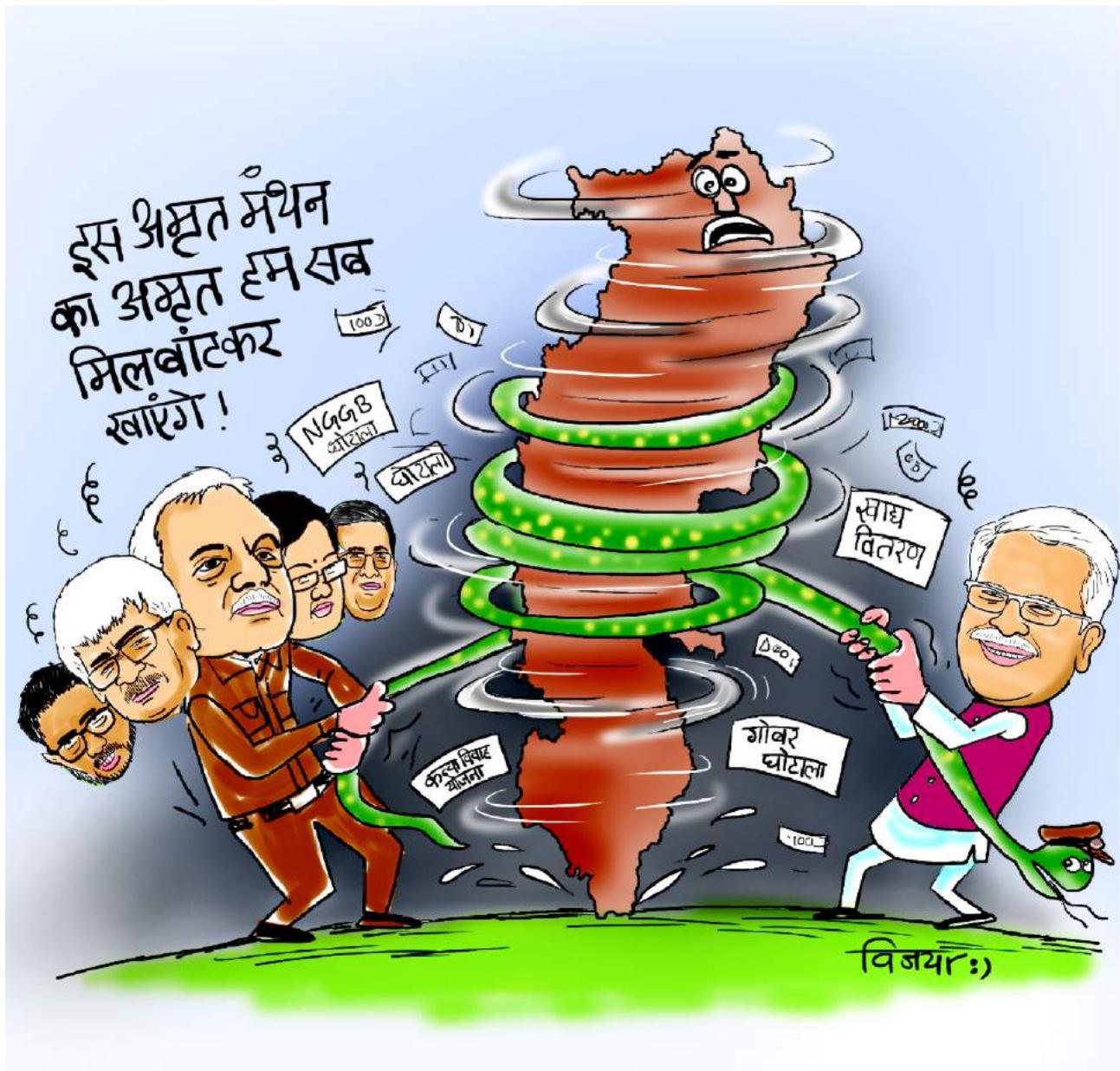
छाता लगाओ और पट पाओ

चुनावों से जोड़ कर देखा जा रहा है। आयकर विभाग ने लिखा है कि, करीब दो सौ करोड़ से ज्यादा के संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं। विज्ञाप्ति में सरकारी अधिकारियों को नगद भुगतान किए जाने का भी उल्लेख है, ऐसा लगता है कि अधिकारियों का कोई समूह वह भी हैं जो सूर्यकांत और उनके सहयोगियों द्वारा लाभान्वित हुआ है। जबकि एक अधिकारी से संबंधित ब्यौरा है कि 50 एकड़ से अधिक अचल संपत्ति में उसके कथित मालिकों द्वारा किए गए निवेश की जांच जारी है।

के कुछ अधिकारियों से दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। केस दर्ज होते हैं। पत्रकार को सैनिटाइजर पिलाया जाता है।

यह सब भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ मॉडल की सच्चाई है। कुल मिलाकर वर्तमान में आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में

लूटपाट का ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें आदिवासियों के हक्कों को मारा जा रहा है। उनके हक के पैसों को बाहर के



प्रदेशों में लुटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ही ऐसा प्रदेश है जहां की सरकार उत्तरप्रदेश, हरियाणा और असम जैसे प्रदेशों के लिए अपने प्रदेश का पैसा फिजूलखड़ी में खर्च कर रही है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस हाइकमान भूपेश बघेल की कारगुजारियों पर अंकुश लगाकर कोई बड़ा एक्शन ले। एक्शन ऐसा हो कि प्रदेश की जनता में एक सटीक संदेश जाये। अब

दिल्ली मीडिया में चमकाते हैं भूपेश अपनी छवि

राज्य के विधानसभा चुनाव में सिर्फ डेढ़ साल का समय बचा है। कहीं ऐसे ही बघेल अपनी मनमर्जी चलाते रहे तो वह दिन दिन दूर नहीं जब एक और प्रदेश कांग्रेस के हाथ से चला जायेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2023 में भूपेश सरकार को वापस सत्ता में लौट पाना मुश्किल हो जायेगा। बल्कि कहीं ऐसा ना हो की उससे पहले ही सत्ता सुख चला जाए। दिसंबर 2018 में जब

खनिज संपदा की लूटमार और आदिवासियों के हकों पर भूपेश का डाका

खनिज संसाधन में छत्तीसगढ़ की अलग पहचान है। इन खनिज संसाधन ही राज्य की आय का मुख्य स्रोत हैं। देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ खनिज संपदा में आत्मनिर्भर है और कई राज्यों की पूर्ति भी यहीं से होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस संपदा पर डाका डाला जा रहा है। खनिज पदार्थों से परिपूर्ण खदानों को राज्य की भूपेश सरकार औने-पौने दाम पर या तो बेच रही है या फिर लीज पर दे रही है। जिसके चलते इस आदिवासी बाहुल्य राज्य की आदिवासी लोग अपनी रोजी-रोटी से मोहताज हो रहे हैं। साथ ही बन्यजीवों के संरक्षण पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्तमान में हसदेव की कोयला खदान का मामला सुर्खियों में है। हसदेव की दो खदानों को तमाम विरोधों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उदयोगपति गौतम की कंपनी को दे दिया है। जिसका बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। राज्य सरकार के कहने पर ही भारत सरकार की संस्था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हसदेव अरण्य का अध्ययन किया है और पिछले साल ही अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहां एक भी कोयला खदान को मंजूरी देने के विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसे रोक पाना असंभव होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अनुसार मध्यभारत का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य के इलाके में



यह वही जंगल है, जिसे खोदकर, अडानी की कम्पनी कोयला निकालेगी। इस हरे-भरे जंगल में शाल, शीशम जैसे दुर्लभ पेड़ लगे हुए हैं, इसके अलावा कई प्रमुख उत्पाद भी मिलते हैं।

नये खदान की मंजूरी से जंगल का विनाश तो होगा ही, जंगल में रहने वाले हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे जानवरों का भी जीवन खतरे में आ जाएगा। साथ ही हाथी मानव संघर्ष बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की मार झेल रहे मध्य भारत के सबसे घने जंगलों के विनाश से तापमान में और ज्यादा वृद्धि होगी। इसके अलावा पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी जंगलों के दोहन को लेकर चेतावनी दी है। इसके बाद भी राज्य सरकार ने कोल आवंटन की मंजूरी दे दी है। जबकि, स्थानीय आदिवासी हसदेव अरण्य को

भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तब किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक जुझारू सा दिखने वाला कांग्रेस नेता पौने चार साल की

सत्ता के बाद देश का सबसे पैसे वाला कांग्रेसी बन जायेगा, वो भी पूरा छत्तीसगढ़ को लूटकर। 15 साल बाद सत्ता में लौटी

भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने आते ही राज्य में अंधाधुंध लूट मचा रखी है। राज्य के अंदर सरकार के संरक्षक अफसरों

बचाने के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं।

लेमरु को अडानी को देने का फैसला- यह वहीं खदान है जिसे हाथियों के लिए रिजर्व रखा गया था। इसके अलावा पूर्व बीजेपी सरकार ने जब इसी लेमरु को अडानी को देने का फैसला किया था उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था और तो और स्वयं राहुल गांधी दो दिन के प्रवास पर छत्तीसगढ़ में आकर रुककर इसका विरोध किया था। आज उसी लेमरु खदान को भूपेश बघेल अडानी को देने जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है भूपेश बघेल भी राहुल गांधी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी करने पर उतारू हो गये हैं।

हसदेव जंगल कटाई से कई वर्ग होगा प्रभावित- छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच में स्थित है हसदेव अरण्य। लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला यह जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरण्य गोंड, लोहार और ओरांव जैसी आदिवासी जातियों के 10 हजार लोगों का घर है। यहां 82

तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें से 18 वनस्पतियों खतरे में हैं। वहीं, सरकारी आंकड़ों की मानें तो इस के लिए लगभग 95 हजार पेंडों की कटाई की जाएगी। वहीं, वहां विरोध कर रहे स्थानीय ग्रामीणों



की मानें तो इसके लिए लगभग दो लाख पेंड काटे जाएंगे।

क्या है हसदेव अरण्य?

यह जंगल छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच में स्थित है। लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में

सहित मंत्री, नेता, अफसर और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार का आतंक मचा दिया है। भूपेश बघेल सरकार जनता से अवैध

वसूली से लेकर विभागों के टेंडर घोटाले, कारोबारियों से अड़ीबाजी, यहां तक कि प्रदेश की भोली-भालि जनता से भी पैसे

लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है।

किसानों का हितेष्ठी बताना, भूपेश बघेल का एक ढांग

फैला यह जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है।

एक दशक से चल रहा है हसदेव बचाओ आंदोलन

पिछले 10 सालों में हसदेव के अलग-अलग इलाकों में जंगल काटने का विरोध चल रहा है। कई स्थानीय संगठनों ने जंगल बचाने के लिए संघर्ष किया है और आज भी कर रहे हैं। विरोध के बावजूद कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिए जाने की वजह से स्थानीय लोग और परेशान हो गए हैं। आदिवासियों को अपने घर और जमीन गंवाने का डर है। वहीं, हजारों परिवार अपने विस्थापन को लेकर चिंतित हैं।

दान के लिए काटे जाएंगे लाखों पेड़

कोल ब्लॉक के विस्तार की वजह से जंगलों को काटा जाना है। सरकारी अनुमान के मुताबिक, लगभग 85 हजार पेड़ काटे जाएंगी। वहीं स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि हसदेव इलाके में कोल ब्लॉक के विस्तार के लिए 2 लाख से साढ़े चार लाख पेड़ तक काटे जा सकते हैं। इससे न सिर्फ बड़ी संख्या में पेड़ों का नुकसान होगा बल्कि वहाँ रहने वाले पशु-पक्षियों के जीवन पर भी बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा।

राजस्थान के लिए हुआ है कोल ब्लॉक का आवंटन

छत्तीसगढ़ और सूरजपुर जिले में परसा कोयला खदान का इलाका 1252.447 हेक्टेयर का है। इसमें से 841.538 हेक्टेयर इलाका जंगल में है। यह खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित है। राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम उसके हवाले कर दिया है। इसके अलावा, राजस्थान को ही केते बासन का इलाका भी खनन के लिए आवंटित है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने खदानों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। पहले से ही काटे जा रहे जंगलों को बचाने में लगे लोगों के लिए यह विस्तार चिंता का सबब बन गया है। इसके लिए,



जगत विज्ञन पत्रिका की संपादक विजया पाठक के साथ मणिशंकर पांडे ब्यूरो चीफ, जगत विजन ने ग्राउण्ड जीरो पर जाकर जायजा लिया। पीछे के तरफ परसा खदान 1 है, जिस पर काम चालू है और आगे की ओर दूसरी खदान का आवंटन अडानी को होना है।

स्थानीय लोग जमीन से लिए अदालत तक लड़ाइयां लड़ रहे हैं।

कई गांव और लाखों लोग होंगे प्रभावित

खदान के विस्तार के चलते लगभग आधा दर्जन गांव सीधे तौर पर और डेढ़ दर्जन गांव आंशिक तौर पर प्रभावित होंगे। लगभग 10 हजार आदिवासियों को डर है कि वे अपना घर गंवा देंगे। अपने घर बचाने के लिए आदिवासियों ने दिसंबर 2021 में पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन सरकार नहीं मानी और अप्रैल में आवंटन को मंजूरी दे दी।

बहद खास क्यों है हसदेव अरण्य

साल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के केवल 1 फीसदी हाथी ही छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन हाथियों के खिलाफ अपराध की 15 फीसदी से यादा घटनाएं यहीं दर्ज की गई हैं। अगर नई खदानों को मंजूरी मिलती है और जंगल कटते हैं तो हाथियों के रहने की जगह खत्म हो जाएंगी और इंसानों से उनका आमना-सामना

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यह प्रदेश एक खेती प्रधान प्रदेश है। यहीं कारण है कि राज्य सरकार की

आय का प्रमुख साधन खेती से ही आती है। प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत लोग खेती किसानी से ही अपना गुजर बसर करते हैं।

लेकिन भूपेश सरकार की कारगुजारियों के चलते इन किसानों का जीवनयापन दुविधा में है। फसलों का सही दाम न मिलना, खाद

और संघर्ष बढ़ जाएगा। यहां मौजूद वनस्पतियों और जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है।

पेसा कानून का हवाला दे रहे हैं आदिवासी

आदिवासियों के मुताबिक, पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरिया (पेसा) कानून 1996 के तहत बिना उनकी मर्जी के उनकी जमीन पर खनन नहीं किया जा सकता। पेसा कानून के मुताबिक, खनन के लिए पंचायतों की मंजूरी ज़रूरी है। आदिवासियों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी दिखाई जा रही है वह फर्जी है। आदिवासियों का कहना है कि कम से कम 700 लोगों को उनके घरों से विस्थापित किया जाएगा और 840 हेक्टेयर घना जंगल नष्ट हो जाएगा।

आखिर हसदेव जंगल कटाई का क्या है मामला- छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। जिसके तहत हसदेव क्षेत्र में स्थित परसा कोल ब्लॉक, परसा ईस्ट और केते बासन कोल ब्लॉक का विस्तार किया जाना है। इस विस्तार के लिए हजारों लाखों पेड़ों की बलि चढ़ानी होगी। यानी कि जंगलों की कटाई की जाएगी।

अडाणी ग्रुप करेगा खनन : सरगुजा और सूरजपुर जिले में परसा कोयला खदान का इलाका 1252.447 हेक्टेयर का है। इसमें से 841.538 हेक्टेयर जंगल में है। यह खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित है। राजस्थान की सरकार ने अडाणी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम उसके हवाले कर दिया है। मतलब इस जगह अडाणी क खनन करेगा।

पहले से ही कोयले की 23 खदानें मौजूद- हसदेव अरण्य क्षेत्र में पहले से ही कोयले की 23 खदानें मौजूद हैं। साल 2009 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे नो गो जोन की कैटगरी में डाल दिया था। इसके बावजूद कई माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी



परसा केते बासन कोल परियोजना से स्थानीय निवासी कितने प्रभावित हैं कि प्रत्येक दिन रैली, प्रदर्शन और पदयात्रा करने को मजबूर हैं तकि उनकी आवाज को सुना जा सके।

गई।

ऐसा है हसदेव अरण्य का संकट- साल 2010 में नो-गो क्षेत्र घोषित होने के बाद कुछ समय के लिए यहां हालात सामान्य रहे। केंद्र में सरकार बदली तो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोयला खदानों का आवंटन शुरू हुआ। ग्रामीण इसके विरोध में आंदोलन करने लगे। 2015 में राहुल गांधी इस क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों का समर्थन किया और कहा कि इस क्षेत्र में खनन नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली लेकिन इस क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर रोक नहीं लग पाई। भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद ने एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक हसदेव अरण्य क्षेत्र को कोयला खनन से अपरिवर्तनीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई कर पाना कठिन है। इस अध्ययन में हसदेव के परिस्थितिक महत्व और खनन से हाथी मानव द्वांद के बढ़ने का भी उल्लेख है।

क्या है नो गो एरिया का मामला- सरगुजा और कोरबा जिलों

बीज की अनुपलब्धता और बिजली जैसे किसानी की प्रमुख ज़रूरतों पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। जिसके चलते आज

छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है। किसान प्रधान प्रदेश होने के कारण 2018 के पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों का

कर्जा माफ करने की भी बात कहीं थी लेकिन अब सरकार को चार साल होने को हैं लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ

जैसा जगत विज्ञन मासिक पत्रिका की संपादक विजया पाठक को बताया -

फर्जी ग्राम सभा हुई, डरा, धमकाकर सहमती ली

रामलाल सिंह कुरियाम, ग्राम सालनी, समिति के कार्यकर्ता, पढ़ाई-संस्कृत में एम.ए.,



संहिता में आये थे। उन्होंने आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन किया। हम इनको छोड़कर नहीं जायेंगे। 2012-13 में परसाई, केतीवासा में ग्रामसभा हुई थी। ग्रामसभा में जो शर्तें थीं, उन में से उन्होंने कोई भी मांग पूरी नहीं की। जब हमने अपनी बात रखी तो इन्होंने कई लोगों को जेल में डाल दिया।

में स्थित हसदेव अरण्य वन क्षेत्र मध्य भारत के सबसे समृद्ध और पुराने जंगलों में गिना जाता है। पर्यावरण के जानकार इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहते हैं। 2010 में इस क्षेत्र को नो गो एरिया घोषित कर दिया गया था। जब जयराम रमेश केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे तो वे नो गो एरिया का कॉन्सेप्ट लाए थे। यानी इस सीमा के आगे खदानों को अनुमति नहीं दी जाएगी। उस लक्ष्मण रेखा का पालन करना जरूरी है।

खनन के लिए आदिवासियों की मंजूरी जरूरी- आदिवासियों के मुताबिक पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल्ड एरिया (पेसा) कानून 1996 के तहत बिना उनकी मर्जी के उनकी जमीन पर खनन

भाजपा जैसा ही कांग्रेस का रवैया है। भाजपा के समय में आंदोलन करना मुश्किल हो रहा था। अब हम कांग्रेस के समय में विरोध कर पा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अगर हमें मुख्यमंत्री साथ देंगे तो हम जीत सकते हैं। ग्रामसभा फर्जी हुई है। भाजपा के समय में एसडीएम ने उदयपुर रेस्ट हाउस में सरपंच लुनिया बाई, सचिव, क्षेत्रपाल को बुलाया, वहां उनको डराया, धमकाया और उनसे सहमति ले ली। तीन बार ग्रामसभा में विरोध हुआ तो यह दमनात्मक और दादागिरी से हस्ताक्षर करवाये। पूरा गांव विरोध कर रहा है। 19 मार्च 2019 को सरकार के कुछ लोग फोर्स लेकर फतेहपुर में जमीन अधिग्रहण करने के लिये जबरदस्ती घुसे। एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, पटवारी काफी लोग थे।

ग्रामवासियों ने उन्हें वहां से भगाया। ये सब लोग चुनाव आचार संहिता में आये थे। उन्होंने आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन किया। हम लोग सामूहिक रूप से पूजा-पाठ करते हैं। इन्हीं गांवों में हमारे भगवान हैं। हम इनको छोड़कर नहीं जायेंगे।

नहीं किया जा सकता। पेसा कानून के मुताबिक, खनन के लिए पंचायतों की मंजूरी जरूरी है। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी ली ही नहीं गयी, जो कागज दिखाया जा रहा है वो फर्जी है। आदिवासियों का कहना है 700 लोगों को उनके घरों से विस्थापित किया जाएगा और 840 हेक्टेयर घना जंगल नष्ट होगा।

हसदेव की खदान आवंटन की कहानी- छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह की सरकार थी। उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को प्रदेश में तीन कोयला जिसमें से दो खदान के माइन डेवलपर कम ऑपरेटर हैं उनकी आवंटन करने की प्रक्रिया चल रही थी। खदान आवंटित भी हो गई लेकिन एनओसी नहीं मिलने के कारण खदान

है। इससे ही लगता है कि अपने आपको किसान, किसान पुत्र और किसान हितैषी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का

सिर्फ ढोंग है। आधिकारक खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का असली चेहरा सामने आ

गया है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार किसानों की कितनी चिंता है उसका पता कुछ महिने पहले चल गया।



हसदेव बचाओ आंदोलन के समर्थन में सोशल एकिटिविट गेधा पाटकर

चालू नहीं हो पायी थी। एनओसी मिलती इससे पहले रमन सरकार चली गई और इसी बीच प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार बन गई। भूपेश सरकार में इन तीन खदानों के आवंटन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर खबर विरोध प्रदर्शन हुए। स्थानीय स्तर पर भी कई स्वयंसेवी संगठनों में विरोध किया। लैकिन लगभग तीन साल बाद 2022 में भूपेश सरकार ने तमाम बाधाओं को दूर करते हुए और तमाम विरोधों के बाद अडानी ग्रुप को हसदेव क्षेत्र की तीन कोयला खदानों पर कार्य करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि इन खदानों को आवंटित करने का विरोध राहुल गांधी ने भी किया था। पर भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की बात को भी नहीं माना। वर्तमान में इन खदानों पर ग्राम पंचायत द्वारा रोक लगाइ गई है। हो सकता है कि आने वाले समय में इन खदानों का आवंटन खतरे में पड़ सकता है। राहुल गांधी ने 23 मई 2022 को लंदन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में युवाओं से बातचीत के दौरान हसदेव जंगल कटाई के बारे में प्रश्न पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी के हसदेव कोयला

जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने गये किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में कई किसान घायल

हो गए। किसानों के साथ पशुओं के समान बर्ताव किया गया। जैसे पशुओं के लिये बाड़ा बना दिया जाता है वैसे ही किसानों को

विस्तार योजना पर दिक्कत है।

राज्य में खनिजों की बहुलता एवं विविधता के साथ बैलाडीला का विश्व विख्यात लौह भण्डार राज्य की धरोहर है। प्रदेश में कोयला, बाक्साइट, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट का बाहुल्य है तथा सामरिक महत्व में टिन अयस्क का पूरे राष्ट्र में छत्तीसगढ़ एकमात्र उत्पादक राज्य है। यहाँ देश की कुल कोयला का 17 प्रतिशत, लोहा अयस्क का 18.67 प्रतिशत भण्डार तथा टिन अयस्क का 37.69 प्रतिशत भण्डार उपलब्ध है। देश के लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ की सहभागीता 14.02 प्रतिशत है। लौह अयस्क के उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। अन्य खनिजों में क्वार्टजाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान, टिन के उत्पादन में प्रथम स्थान, डोलोमाइट में प्रथम स्थान, बाक्साइट में पंचम स्थान एवं चूना पत्थर के उत्पादन में सातवें स्थान पर है।

छत्तीसगढ़ शासन की खनिज नीति की घोषणा 01 नवम्बर 2001 को की गई, जिसमें कहा गया, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य इसके विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सामाजिक धरोहर का सम्पोषण तथा बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदाओं का समुचित दोहन करना है। राज्य का 44 प्रतिशत से अधिक भाग वनों से आच्छादित है तथा अधिकांश खनिज पदार्थ इन्हीं वन प्रान्त एवं पहाड़ियों में पाये जाते हैं। यदि इस नवजात प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा, खनिज सम्पदा का दोहन कठिन वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों के कारण नहीं हो पाएगा तो इस नवीन राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा।

भारत के सन्दर्भ में यह बात कही जाती है कि प्रकृति ने उदारतापूर्वक खनिज संसाधनों का उपहार दिया है, परन्तु भारतवासी इनसे समुचित लाभ लेने में असमर्थ रहे हैं। यहीं बात छत्तीसगढ़ राज्य पर भी लागू होता है। खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधनों, विस्तृत उपजाऊ भूमि, जीवन रेखा महानदी, वन सम्पदा आदि के विद्यमान रहते हुए भी आज यहाँ का आर्थिक विकास निम्न है, विकास की प्रक्रिया तेज नहीं हुई है। तथा स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए खनिज पदार्थों के समुचित विदोहन की आवश्यकता है। खनिज पदार्थों से प्राप्त होने वाली आय छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है।

आगे बढ़ने से रोकने के लिये बाड़ा बना दिया गया। किसान अपनी 09 मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। किसानों के ऊपर



छत्तीसगढ़ राज्य की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार उद्यमियों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 27 प्रतिशत राजस्व खनिजों के उचित दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है।

देश के बड़े उद्योगपति से मिली 25,000 करोड़ की दान दक्षिणा ?

विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल जिस गौतम अदानी को पानी पी-

पी कर दिन रात कोसा करते थे। आज वर्ही अदानी बघेल की कृपापात्र से छत्तीसगढ़ की प्रमुख हसदेव कोयला की दोनों खदानों का कॉन्ट्रैक्टर है। सूत्रों का कहना है इस खदान डील में भूपेश बघेल को लगभग 25,000 करोड़ की दान दक्षिणा भी मिली है। इसमें से कुछ राशि (करोड़ों में) दिल्ली के किसी सुब्रत (सहाराश्री नहीं) के हाथों से पहुंचावा भी दिया गया है। निश्चित तौर पर 2023 के बाद बघेल को देश का सबसे अमीर कांग्रेसी बनने का ताज मिलेगा। यह ताज हमर छत्तीसगढ़ को लूटकर ही मिलेगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर दुर्व्यहार किया गया। दरअसल किसानों का एक बड़ा जत्था राहुल गांधी से मिलने एयरपोर्ट

पहुंचा था। हजारों की संख्या में किसानों को देख पुलिस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर न सिर्फ किसानों को राहुल गांधी

से मिलने से रोकने की कोशिश की बल्कि उनके साथ सख्ती का प्रदर्शन भी किया। किसानों के साथ हर मुद्दे से कंधे से कंधा

सिर्फ कागजों तक सिमटा भूपेश का छत्तीसगढ़ मॉडल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल इन दिनों कारनामों के लिए चर्चा में है। इस छत्तीसगढ़ मॉडल में लूट है, अष्टाचार है, बेर्झमानी है, अत्याचार है, अन्याय है। इस मॉडल के नाम पर भूपेश बघेल पूरे राज्य को गर्त में ले जाने के लिए तैयार है भूपेश बघेल भले ही यह कहते नहीं थक रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल से प्रदेश का विकास हो रहा है लेकिन हकीकत में यह विनाश ही कर रहे हैं। कुछ कारनामे तो ऐसे हैं कि जिनका जिक्र करते ही सारी सच्चाई सामने आ जाती है। अपनी झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में भूपेश बघेल कांग्रेस हाईकमान के सामने भी गलत जानकारियां देते हैं।



छत्तीसगढ़ मॉडल की तस्वीर बयां करते ये सङ्करों पर किसान

किसान और खेती छत्तीसगढ़ की असल पूँजी हैं। इनकी बेहतरी और खुशहाली से ही राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया जा सकता है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान भूपेश सरकार ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की रूपरेखा बनाई जिससे गांव गतिमान हो जाए। लेकिन सरकार की सुस्त व्यवस्था और कुशासन से छत्तीसगढ़ मॉडल राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुष्टि और पल्लवित नहीं कर सकी। गांव, ग्रामीणों और किसानों की तस्वीर और तकदीर में सुखद बदलाव दिखाई नहीं दिये। सरकार ने तो वादा किया था कि छत्तीसगढ़ सरकार की गांव, गरीब, किसान, व्यापार और उद्योग हितैषी नीतियों से समाज के सभी वर्गों में खुशहाली लायेगी। धन और तेंदूपत्ता की देश में सबसे अधिक कीमत पर खरीदी, किसानों की कर्ज माफी, सिंचाई कर की माफी, सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। अष्टाचार और लूट के कारण आज यह छत्तीसगढ़ मॉडल सिर्फ कागजों भर में मिल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नया आर्थिक मॉडल अपनाया है, उसमें ग्रामीण विकास एवं औद्योगिक विकास के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर सुलभ होने थे। राज्य के किसानों का लगभग 09 हजार करोड़ रूपए का कृषि ऋण माफ होना था। समर्थन मूल्य पर धन खरीदी, किसानों के ऊपर वर्षों से बकाया सिंचाई कर, राज्य के 05 लाख 81 हजार से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क एवं रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराना था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों के श्रम का सम्मान करना था तथा योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष लगभग 5700 करोड़ रूपए की राशि आदान सहायता प्रदान करना था। इसका सीधा लाभ खेती-किसानी और किसानों को होना था। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह छत्तीसगढ़ मॉडल सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। जमीनी स्तर पर देखे को लोगों की, किसानों की आर्थिक हालत पहले से और ज्यादा खराब हो गई है।

लगाकर लड़ने वाले राहुल गांधी को उनके ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीचा दिखा दिया। इस पूरे वाक्या के पीछे

की कहानी कुछ और ही थी। भूपेश बघेल को इस बात का भय था कि कहीं किसान राहुल गांधी से मिलकर राज्य में फैले

अष्टाचार और किसानों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार का भांडा न फोड़ दें। इसलिए भूपेश बघेल ने किसानों को राहुल

छत्तीसगढ़ में फिर हलचल, मंत्री टीएस सिंह देव ने मंत्री के पद से दिया इस्तीफा



छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस सरकार के अंदर चल रही खींचतान सङ्कों पर आ गई है। पार्टी के दिग्गज नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने पंचायत और ग्रामीण विभाग की अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। उनके इस्तीफे से सरकार और संगठन में खलबली मच गई है। इसके साथ ही अब प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार में आने

वाले समय में संकट के बादल मंडराने का खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महिनों से राज्य में सत्ता को लेकर भूपेश बघेल और सिंहदेव बाबा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। कारण था सीएम की कुर्सी पर ढाई ढाई साल का मसला। यह मसला पार्टी हाईकमान तक पहुंचा था लेकिन उस समय तो यह मामला काफी हद तक सुलझ गया था लेकिन

गांधी से नहीं मिलने दिया। दरअसल कई सालों से लंबित अपनी 09 मांगों को लेकर नवा रायपुर क्षेत्र के 27 गांवों के किसान

आंदोलन कर रहे हैं।

राज्य बनने के बाद से अब तक 18 से अधिक वर्ष बीत गए। प्रदेश सर्वाधिक तेजी

से विकसित होने वाले राज्यों के सूची में शामिल रहा, लेकिन इसके बावजूद यहां के मूल निवासी एवं रहवासियों को विकास का

सिंहदेव बाबा के इस्तीफे ने एक बार फिर इसे हवा दे दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ तनातनी में फंसे राज्य सरकार के मंत्री टी. एस. सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने चार पत्रों के इस्तीफे में सिंहदेव ने संकेत दिया है कि उन्हें सरकार में दरकिनार किया जा रहा है, हालांकि वह अन्य चार मंत्रालयों का पदभार संभालते रहेंगे। प्रदेश में कांग्रेस का 15 वर्षों का बनवास समाप्त कराने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिंहदेव के इस कदम ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसमें उनकी उपेक्षा और अपमान का दर्द छलका है।

मंत्री सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपे चार पत्रों के इस्तीफे में विभाग और सरकार के कामकाज पर असंतोष जाहिर किया है। बघेल को भेजे गए इस्तीफे सिंहदेव ने कहा है, मैं पिछले तीन साल से अधिक समय से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भारसाधक मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। इस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बर्नी, जिनसे मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूं। सिंहदेव ने लिखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवास विहीन लोगों को मकान बनाकर दिया जाना था जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटित करने का अनुरोध किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कारण राज्य के करीब आठ लाख लोगों के लिए मकान नहीं बन सके। इसके अतिरिक्त 08 लाख घर बनाने में से करीब 10 हजार करोड़ रूपये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहायक होते। मुझे दुःख है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के आवास विहीन लोगों को नहीं मिल सका। हमारे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य अंतर्गत ग्रामीण आवास का अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है। मंत्रालय के कामकाज के संबंध में सिंहदेव ने कहा, किसी भी विभाग में विवेकाधीन योजनाओं के तहत

काम की स्वीकृति का अनुमोदन उस विभाग के भारसाधक मंत्री का अधिकार होता है। लेकिन मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत कार्यों की अंतिम स्वीकृति के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस के विपरीत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गयी। कार्यों की स्वीकृति के लिए मंत्री के अनुमोदन उपरांत अंतिम निर्णय मुख्य सचिव की समिति द्वारा लिए जाने की प्रक्रिया बनाई गई जो प्रोटोकॉल के विपरीत और सर्वथा अनुचित है। लेकिन बार-बार लिखित आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिंहदेव ने अपने इस्तीफा में पेसा कानून को लेकर बनाए गए नियमों में बदलाव पर भी आपत्ति जतायी है और कहा कि इसमें भारसाधक मंत्री को विश्वास में नहीं लिया गया है। इस्तीफे में मंत्री ने कहा है, जन घोषणा-पत्र में किए गए वादों में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू करना शामिल था। इसके लिए मैंने आपसे कई बार चर्चा की, विभागीय पहल भी की लेकिन इसपर अभी तक कोई सहमति सकारात्मक पहल नहीं हो पायी है। सिंहदेव ने आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत मनरेगा का काम करने वाले रोजगार सहायकों से हड़ताल करवाकर राज्य में मनरेगा के कार्यों को प्रभावित किया गया जिसमें सहायक परियोजना अधिकारियों (सर्विदा) की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आयी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, आपने खुद हड़तालरत कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिए एक कमेटी गठित की, लेकिन हड़ताल वापस नहीं ली गई। इस कारण करीब 1250 करोड़ रुपए का मजदूरी भुगतान प्रभावित हुआ और धन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नहीं पहुंच सका। सिंहदेव ने इस्तीफा में कहा है जन-घोषणा पत्र के विचार धारा के अनुरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मत है कि विभाग के सभी लक्ष्यों को समर्पण भाव से पूर्ण करने में वर्तमान परिस्थितियों में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं।

वो लाभ नहीं मिल सका, जिनके बे हकदार थे। गिरता हुआ भू-जल स्तर, खेती में लागत की बढ़ोत्तरी, मवेशी के लिए चारा

संकट, महंगाई आदि ने स्थिति को और भयावह बना दिया। छत्तीसगढ़ की 80 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है, उसके

बावजूद सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि को अनदेखा किया। पिछले 15 वर्षों में ढांचागत (भवन, फ्लाईओवर,

भूपेश बघेल नहीं बना पाए नक्सली समस्या को लेकर कोई रणनीति

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को बने लगभग साढ़े तीन साल हो गए हैं। इन साढ़े तीन साल में भूपेश बघेल ने राज्य की सबसे प्रमुख समस्या नक्सलवाद को लेकर किसी भी प्रकार की गंभीरता नहीं दिखाई है। न ही नक्सलवाद को जन्म दे रहे कारणों पर कोई रणनीति बनाई है। जिससे एक बार फिर राज्य का आदिवासी समुदाय अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जबकि 2018 के पहले कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थीं और नक्सलियों की समस्याओं को खत्म करने का आश्वासन दिया था।

2018 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसे 2013 में झीरम घाटी में माओवादी हमले में मारे गये कांग्रेस नेताओं को समर्पित किया गया था। इस घोषणा पत्र के क्रमांक 22 पर दर्ज है, नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जाएगी और वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये दिए जायेंगे, जिससे कि विकास के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। कांग्रेस पार्टी को राज्य में भारी बहुमत मिला और 15 सालों तक सत्ता से बाहर रहने के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस पार्टी के मुखिया भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2018 की जिस शाम को शपथ ली थी, उसी रात इस जन घोषणा पत्र की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को



सड़कों का जाल बिछाना) निर्माण, खनन क्षेत्र विस्तार आदि पर ध्यान दिया गया। इससे गैर बराबरी के विकास से समाज में असंतुलन पैदा हुआ, खेती चौपट हुई और अधिकांश लोग किसान से खेतीहर मजदूर बन गए और कर्ज में दबे कई किसानों को

आत्महत्या तक करनी पड़ी। ऐसे में आम छत्तीसगढ़िया खुद को विकास के नाम पर ठगा सा महसूस करने लगे।

नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी की विफलताएं

गांव में स्वावलंबन और अर्थिक

सौंपी। शपथ वाले दिन ही मंत्री परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में लिए गये तीन फ़ैसलों में एक फ़ैसला था- झीरम घाटी कांड की एसआईटी जांच। बस्तर की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को भारत में किसी राजनीतिक दल पर माओवादियों के इस सबसे बड़े हमले में राज्य में कांग्रेस पार्टी की पहली पक्की के अधिकांश बड़े नेताओं समेत 29 लोग मारे गये थे। अब, जबकि इस घोषणा पत्र और सरकार के फ़ैसले को लगभग साढ़े तीन साल होने को आये, झीरम घाटी की जांच अदालतों में उलझी हुई है और नक्सल समस्या की किसी घोषित नीति का कहीं अता-पता नहीं है। वार्ता शुरू करने के किसी प्रयास का कोई ब्लूप्रिंट अब तक सामने नहीं आया है। इसके उलट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई अवसरों पर कह चुके हैं कि उन्होंने

गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने सुराजी गांव योजना नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी लेकर आयी थी। जिसका मूल उद्देश्य था कि विकास से स्थानीय संसाधनों के संरक्षण और विकास में लोगों की भागीदारी बढ़े। गांवों में बने

माओवादियों से वार्ता करने की बात कभी नहीं कही थी, पीड़ितों से वार्ता करने की बात कही थी। नक्सली भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं। लेकिन कोई भी सरकार उन्हें इस दिशा में लाने का प्रयास ही नहीं करती है। जगत विजन पत्रिका ने कुछ समय एक स्टोरी प्रकाशित की थी। जिसमें बताया गया था कि कैसे नक्सली सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और किस कारण से वह सरकार के खिलाफ रहते हैं। गौरतलब है कि जब प्रदेश में रमन सरकार थी तब विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल ने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार आते ही नक्सलियों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा। आज जब प्रदेश में उनकी ही सरकार है तो वह अपने वादे से मुकर गए हैं।

सरकार के दावों पर सवाल

संदिग्ध माओवादियों से मुठभेड़ में सुरक्षाबल के जवानों की मौत ने सरकार के उन दावों को ग़लत साबित कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि पिछले दो साल में माओवादी कमज़ोर हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दाहराया है कि माओवादी सीमित क्षेत्र में सिमटकर रह गये हैं और वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बीजापुर में माओवादियों ने ज़िला पंचायत के सदस्य बुधराम कश्यप की हत्या कर दी। माओवादियों ने कोडागांव ज़िले में सड़क निर्माण में लगी एक दर्जन से अधिक गाड़ियों को आग लगा दी। नारायणपुर ज़िले में माओवादियों ने सुरक्षाबल के जवानों की एक बस को विस्फोटक से उड़ा दिया, जिसमें 5 जवान मारे गए। इसी तरह दंतेवाड़ा में पुलिस ने दो माओवादियों को एक मुठभेड़ में मारने का दावा किया। बीजापुर ज़िले में माओवादियों ने पुलिस के जवान सन्तु पोनेम की हत्या कर दी। माओवादी एक के

बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे कहीं से कमज़ोर हुए हैं। सरकार के पास माओवाद को लेकर कोई नीति नहीं है। सरकार की नीति यही है कि हर बड़ी माओवादी घटना के बाद बयान जारी कर दिया जाता है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रही है। कोई नीति होगी तब तो उस पर क्रियान्वयन होगा।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा राज्य के अंतिम छोर पर बसे इलाके हैं और इन्हीं दो ज़िलों की सरहद पर बसा हुआ है टेकलागड़ा



गांव, जहां जहां 2020 में नक्सलियों ने 17 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। असल में माओवादियों का गढ़ कहे जाने वाला इस इलाके में माओवादियों के बटालियन नंबर वन का दबदबा है। इस बटालियन के कमांडर माड़वी हिड़मा को लेकर जितने किस्से हैं, उससे केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि हिड़मा आक्रामक रणनीति का पर्याय है। 90 के दशक में माओवादी संगठन से जुड़े माड़वी हिड़मा ऊर्फ इंदमूल ऊर्फ पोड़ियाम भीमा ऊर्फ मनीष के बारे में कहा जाता है कि 2010 में ताड़पेटला में 76 जवानों

गौठान आजीविका के केंद्र बनें। राज्य के लगभग 7777 से अधिक गौठानों में पशुओं के संरक्षण और संवर्धन की व्यवस्था के साथ ही वहां हरे चारे का उत्पादन, महिला समूह द्वारा सामूहिक रूप से सब्जी की खेती, फलदार पौधों का रोपण

और जैविक खाद के उत्पादन के साथ ही अन्य आय मूलक गतिविधियों के संचालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आधार मिले। नीति आयोग की बैठक में भी इस योजना का जिक्र किया गया था। मुख्यमंत्री खुद इस योजना की मॉनिटरिंग

कर रहे हैं। वर्तमान में प्रथम चरण में यह योजना राज्य के 15 प्रतिशत (1665) ग्राम पंचायतों में लागू की गई थी तथा संचालन की जिम्मेदारी ग्राम समितियों को सौंपी गयी। लेकिन योजना के प्रारंभ से ही इसकी खामियों की चर्चाएं होने लगी। भ्रष्टाचार

की हत्या के बाद उसे संगठन में महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी दी गई। इसके बाद झीरम घाटी का मास्टर माइंड भी इसी हिडमा को बताया गया। इस पर 35 लाख रुपये का इनाम है। हालांकि 2010 से अब तक कम से कम 3 अवसरों पर हिडमा के मारे जाने की खबर आई है।

आदिवासियों की रिहाई अटकी

नई सरकार से लोगों ने भारी अपेक्षा पाल रखी थी लेकिन नई सरकार की प्राथमिकता में आदिवासी अब भी नहीं हैं। वो इसके लिए जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए गठित जस्टिस पटनायक कमेटी का उदाहरण देती हैं। राज्य सरकार ने 2019 में राज्य की जेलों में लंबे समय से बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस एके पटनायक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। आरंभिक तौर पर 4007 आदिवासियों की रिहाई के लिए पटनायक कमेटी ने तीन बिंदु बनाये थे। लेकिन इस कमेटी की पहली बैठक में 313, दूसरी बैठक में 91 और तीसरी बैठक में 197 मामलों पर ही बात हो पाई। इनमें से अधिकांश मामले शराब से जुड़े हुये थे। वहाँ कुछ मामले जुआ और गली-गलौज के थे। पिछले दो सालों में आदिवासियों को कोई बड़ी राहत मिल पाई हो, ऐसा नहीं लगता। बस्तर के इलाके में पेसा कानून को किनारे करके कैंप बनाये जा रहे हैं और आदिवासी इस मुद्दे पर कई जगहों पर प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन उनकी आवाज़ अनसुनी रह गई है। बस्तर में आदिवासियों के साथ सुरक्षाबलों के फर्जी मुठभेड़, बलात्कार, उनके घरों को जलाये जाने के कई मामलों में तो जांच हुई है और अदालतों से लेकर मानवाधिकार आयोग, जनजाति आयोग जैसे संगठनों ने गंभीर टिप्पणियां की हैं, मुआवजे की अनुशंसा की है। सुरक्षाबलों से नाराज़गी के कारणों को अगर चुनी हुई सरकार नहीं समझेगी तो कौन समझेगा?

40 सालों से चल रहा बस्तर का संघर्ष

सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच पिछले 40 सालों से बस्तर के इलाके में संघर्ष चल रहा है। राज्य बनने के बाद से

और प्रशासन की उदासीनता के चलते इसके क्रियावयन में कई बाधाओं को देखा गया है। इसकी विफलताओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी भी प्रदेश की कई गांवों में इस योजना के बारे में पता नहीं है। यह एक ऐसी योजना है

जिसका न तो लक्ष्य निर्धारित है, न तो इसमें बजटीय प्रावधान है, न इसके बारे में न किसी विधायक को मालूम है, न ही सांसद को और न ही डिपार्टमेंट को, न इस संदर्भ में कभी चर्चा की गई है और वे जो करना चाहते हैं, वे गांव में लोग लंबे समय से

करते आ रहे हैं। अतः ऐसी योजना के बारे में क्या कहा जाए।

क्या है नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी योजना? - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही नारा दिया- छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा अउ

बाड़ी एला बचाना हे संगवारी (छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए चार चिन्ह हैं, नरवा (नाला), गरवा (पशु एवं गोठान), घुरवा (उर्वरक) एवं बाड़ी (बगीचा), इनका संरक्षण आवश्यक है। राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से भूजल रिचार्ज, सिंचाई और आर्गेनिक खेती में मदद, किसान को दोहरी फसल लेने में आसानी, पशुओं को उचित देखभाल सुनिश्चित हो सकेगी, परंपरागत किचन गार्डन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएंगी तथा पोषण स्तर में सुधार आएगा।

नरवा- इसके तहत आवश्यकतानुसार नालों तथा नालों में एवं नहरों में चेक डेम का निर्माण किया जा रहा है। ताकि बारिश का पानी का संरक्षण हो सके और बाटर रिचार्ज से गिरते भू-स्तर पर रोक लग सके। इससे खेती में आसानी होगी।

गरवा- इसके तहत गांवों में जो भी पशुधन है उन्हें एक ऐसा डे-केयर सेंटर उपलब्ध करवाना है जिसमें वे आसानी रह सके और उन्हें चारा, पानी उपलब्ध हो। इसके लिए उसके लिए गोठान निर्माण से लेकर आवश्यक संसाधन, जमीन आदि प्रदान किए जा रहे हैं।

घुरवा- यह एक गढ़ा होता है, जिसमें मवेशियों को गोबर एवं मलमूत्र का संग्रहण किया जाता है। जिससे कि गोबर गैस एवं खाद बनाई जा सके।

बाड़ी- यह घर से लगा एक बगीचा है, जिसमें पोषण हेतु फल-फूल उगाई जा सके।

गौधन न्याय योजना

छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना आज पूरे देश में चर्चित हो रही है, पशुपालकों, किसानों और ग्रामीणों के लिए शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रबंधन को बढ़ावा देना है ताकि गांवों में आर्थिक तंत्र को मजबूत किया जा सके और ग्रामीणों को



आत्मनिर्भर। राज्य में पशुधन को संरक्षित एवं संवर्धित करने वालों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरू की गई थी। इस योजना में सरकार पशुपालकों से 02 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रही है। सरकार द्वारा बताया गया है कि खरीदी किए गोबर से गौठानों में संचालित स्व-सहायता समूह की महिलाएं कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, गोबर से गुलाल, जिसे दीया, गमला इत्यादि चीजों का निर्माण करती हैं। गोधन न्याय योजना आज ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों के लिए आमदनी का एक मजबूत जरिया बताया गया है। लेकिन क्या इस योजना से किसी छत्तीसगढ़वासी को लाभ पहुंचा है यह चिंतनीय सवाल है। योजना भले की लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई हों पर जब ऐसी योजनाओं में शासन का लालफीताशही पलीता लग जाता है तो इसके परिणाम सुखद आना मुश्किल है। अभी तक सरकार ने कितने किसानों से कितना गोबर इकट्ठा किया है

और कितनी राशि का भुगतान किया है इसकी जानकारी नहीं है। जिससे ही हम कह सकते हैं कि योजना बनाकर लोगों को गुमराह करना ही भूपेश सरकार की आदत हो गई है।

गोबर प्रदेश में हुई छत्तीसगढ़ की पहचान- छत्तीसगढ़ में झूठ की भी खेती होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तो पूरे देश में जा जाकर गोबर से आमदनी के बारे में बताते हैं। एक न्यूज वेबसाइट में तो इन्होंने गोठान से प्रति माह 15,000-20,000 हजार की आमदनी बता दी। मुख्यमंत्री जी झूठ भी सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को 15,000 के हिसाब से साल का एक लाख अस्सी हजार की कमाई हो जाती है। अगर प्रदेश में एक लाख लोगों से ही गोबर खरीदने में सरकार को 1800 करोड़ रुपये करने होने और अगर दस लाख लोगों से गोबर खरीदा जायेगा तो कुल 18,000 करोड़ रुपये करने पड़ेंगे। धन के पैसे भी इतनी किश्तों में दिए जाते हैं कि किसान उसका असली फायदा ही नहीं ले पाता।

श्रीलंका से सबक



भारत के पड़ोसी देशों पर भी चीन का लगभग आठ लाख करोड़ रूपया का कर्ज है। श्रीलंका पर चीन का पचास हजार करोड़ कर्ज है। पाकिस्तान पर तीन लाख करोड़, नेपाल पर 1.35 लाख करोड़, बांग्लादेश पर नब्बे हजार करोड़ तथा अफगानिस्तान पर लगभग दो लाख करोड़ कर्ज है। श्रीलंका को आर्थिक एवं राजनैतिक हालात बिगड़ने के पीछे एक कारण यह भी है कि श्रीलंका के पास कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है। श्रीलंका ने तो पिछले ही साल विशेष कानून पारित कर चीन को मदद से बनने वाले बंदरगाहों को विशेष छूट दी थी तथा एसईजेड और विदेशी निवेश के नाम पर 996 हेक्टेयर जमीन चीन की लीज पर दे दी थी तथा हम्बन टोटा बंदरगाह को चीन को 66 साल की लीज पर दे दिया था। इनका परिणाम यह निकला की श्रीलंका में महंगाई इतनी बढ़ गई कि जनता को सङ्क पर निकलने के अलावा कोई रास्ता ही शेष नहीं बचा।

रघु ठाकुर

भारत के पड़ोसी देशों में गहरी उथल पुथल है। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालद्वीप, अफगानिस्तान सभी कम या ज्यादा आंतरिक हलचल के शिकार

हैं। पाकिस्तान का सत्ता पलट हो चुका है और श्रीलंका में अभी हाल में एक प्रकार से तख्ता पलट ही हुआ है। यद्यपि पाकिस्तान का तख्तापलट जन आंदोलन से कम इमरान सरकार की अदूरदर्शी नीतियाँ और

तरीकों से अधिक प्रभावित रहा है। इमरान ने राजनीति को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया और वे भारत के खिलाफ शत्रुता की रणनीति और चीन से सहयोग की नीति पर चलते रहे हैं। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार

के खिलाफ जन विद्रोह हुआ है। एक तो राजपक्षे परिवार ने देश के सभी प्रमुख पदों पर कुनबाई कब्जा जमाया था। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण पदों पर उनके ही परिवार के लोग बैठा दिए गए थे। दूसरे श्रीलंका के आर्थिक हालात भी तेजी से बिगड़े हैं। पिछले दो दशक में चीन ने अपनी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था और दुनिया में साहकारी विदेश नीति को अखियार किया था जो भूमिका पहले अमेरिका निभाता था उस भूमिका को चीन ने एक भारत के पड़ोसी देशों पर भी चीन मात्रा में उनकी अंतरिक योजनाओं के लिये कर्ज या पूँजी निवेश के रूप में देना शुरू किया। पिछले 20 वर्षों में चीन ने छोटे देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने उन्हें कर्ज के जाल में फँसाया तथा 164 देशों को पाकिस्तान पर तीन लाख करोड़ लगभग 94000 परियोजनाओं के लिए साढ़े आठ सौ अरब डॉलर कर्ज या पूँजी निवेश के रूप में दिया है। चीन की यह नीति शी जिनपिंग की

महत्वाकांक्षी योजना बनबेल्ट वन रोड के लिए दी गई थी तथा इस प्रकार चीन अपनी वैश्विक आर्थिक भागीदारी साहूकारी तथा कूटनीतिक ताकत और समर्थन को भी बढ़ा रहा था।

भारत के पड़ोसी देशों पर भी चीन का लगभग आठ लाख करोड़ रूपया का कर्ज है। श्रीलंका पर चीन का पचास हजार करोड़ कर्ज है। पाकिस्तान पर तीन लाख करोड़, नेपाल पर 1.35 लाख करोड़, बांग्लादेश पर नब्बे हजार करोड़ तथा अफगानिस्तान पर लगभग दो लाख करोड़ कर्ज है। श्रीलंका को आर्थिक एवं राजनैतिक हालात बिगड़ने के पीछे एक कारण यह भी है कि श्रीलंका के पास कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है। श्रीलंका ने तो पिछले ही साल विशेष कानून पारित कर चीन को मदद से बनने वाले बंदरगाहों को विशेष छूट दी थी तथा एसईजेड और विदेशी निवेश के नाम पर 996 हेक्टेयर जमीन चीन की लीज पर दे दी थी तथा हम्बन टोटा बंदरगाह को चीन को 66 साल

की लीज पर दे दिया था। इनका परिणाम यह निकला की श्रीलंका में महंगाई इतनी बढ़ गई कि जनता को सड़क पर निकलने के अलावा कोई रास्ता ही शेष नहीं बचा। खर्च में कटौती के नाम अनेक देशों के दूतावास बंद करने पड़े। प्रधानमंत्री महेन्द्र राजपक्षे और उनके अनेक परिजनों के इस्तीफे के बाद भी श्रीलंका की स्थिति सामान्य नहीं हुई है। विक्रम रानिले को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है परन्तु उनकी सफलता भी संदिग्ध लगती है, क्योंकि 224 की संसद में श्री विक्रम की पार्टी के वे अकेले सांसद व प्रधानमंत्री हैं। जाहिर है कि यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं चलेगी तथा हालात और बिगड़ेंगे। यद्यपि उन्होंने, राजपक्षे के विरुद्ध चल रहे आंदोलन का समर्थन किया है। जहाँ एक तरफ श्रीलंका के हालात के पीछे प्रत्यक्ष तौर पर आईएमएफ के कर्ज न चुका पाने या चीन के कर्ज की भूमिका नजर आती है वहीं गहराई से देखने पर अन्य कारण भी नजर आएंगे। यद्यपि वे अभी स्पष्ट नहीं परंतु





उनका दूरस्थ प्रभाव तो दिख ही रहा है। श्रीलंका में तमिल विद्रोह व लिट्टे के उभार को सैन्य शक्ति से दबाने का काम श्री महेन्द्र राज पक्षे ने किया था। सिंहलों बनाम तमिल के नस्ली संघर्ष का परिणाम उस समय के हालात थे। लिट्टे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर श्रीलंका की सत्ताल को बंदूक के सहारे हथियाना चाहता था। जबरदस्त आतंकवाद के दौर में राजपक्षे ने हिंसा और ताकत का इस्तेमाल कर लिट्टे को खत्म किया। लिट्टे के मुखिया प्रभाकरन को मारा और यहाँ तक कि इस संघर्ष में प्रभाकरन का दस वर्षीय बेटा भी मारा गया। लिट्टे का संगठनात्मक ढाँचा तो टूट गया परन्तु भीतर जल रही मनों की आग तथा विद्रोह शांत नहीं हुआ। जाहिर तौर पर नहीं परन्तु अवसर और दबे आक्रोश के रूप में श्रीलंका के वर्तमान जन विद्रोह के पीछे यह भी एक कारण है। हालांकि प्रमुख कारण तो महेन्द्रा राजपक्षे का परिवारवाद, तानाशाही रवैया और अमर सत्ता बनाये

रखने की आकांक्षाएं हैं। श्रीलंका के घटनाक्रम से कुछ सबक सीखे जा सकते हैं। श्रीलंका मामले में विदेश नीति बनाते समय भारत को बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि श्रीलंका का नस्लवादी संघर्ष भारत को भी प्रभावित करता है। स्वर्गीय राजीव गांधी अपनी इसी गलत नीति के कारण मौत के शिकार हुए थे। श्रीलंका चीन के आर्थिक कर्जे से मुक्त हो और वैश्विक आर्थिक शक्तियों का खिलौना न बने भारत को यह प्रयास करना चाहिए। दरअसल श्रीलंका की भोगोलिक स्थिति विश्व शक्तियों के लिये मुख्य आकर्षण का केन्द्र है और दक्षिण एशिया पर सामरिक निगरानी के लिए सामरिक केन्द्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष के तौर पर सभी सत्ताधीशों को ये सुझाव हो सकते हैं:

► भारत और किसी भी देश को चीन और वैश्विक आर्थिक शक्तियों के कर्ज से बचना चाहिए। क्योंकि कर्ज स्वतंत्रता के क्षय का कारण बनता ही है।

► विदेशी कर्ज किसी न किसी रूप में विदेशी घुसपैट और हस्तक्षेप का कारण बनता है जो कालान्तर में देशों में जातीय, धार्मिक, नस्ली या अन्य प्रकार के अन्तसंघर्षों के बीज बोता है।

► विदेशी कर्ज देश की आर्थिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाता है और साहूकारों की शर्तों को मानने को लाचार करता है।

► विदेशी पूँजी निवेश और विदेशी कर्ज ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अतः अपनी आजादी कायम करने के लिए विकास के लुभावने एवं विनाशकारी ढाँचे को खड़ा करने के बजाय कम पूँजी के छोटी मशीन और रोजगार पैदा करने वाले विकास को ही आधार बनाना चाहिए। गांधी और लोहिया में रास्ता खोजने से ही वैश्विक समस्याओं का हल हो सकता है।

बारिश, बाढ़ और बर्बादी...



बाढ़ आपदा को योकने में सरकारें नाकाम हैं !

नवीन कुमार शर्मा

भारत में मानसून के आते ही प्राकृतिक आपदाओं की बाढ़ आ जाती है। मानसून के साथ ही आई बाढ़ कई राज्यों की तबाही को कई गुना बढ़ा देती है। हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों घर नष्ट हो जाते हैं, कई हजार हैक्टेयर में फसल तबाह हो जाती है। जानमाल की हानि, इमारतों व घरों का जलमग्न होना, जन स्वास्थ्य को नुकसान, फसलों और खाद्यान्न पूर्ति पर प्रभाव इसके कुछ बुरे पहलू है। इसीलिए हम देश में बाढ़ से आई आर्थिक तबाही और 07 दशक के सैलाब काल की व्याख्या कर रहे हैं और ये

समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर सिस्टम की नाकामी है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ हर साल सबसे ज्यादा कहर बरपाती है। देश में प्राकृतिक आपदाओं के कुल नुकसान का 50 प्रतिशत केवल बाढ़ से होता है। 07 दशक में देश को बाढ़ से 4 लाख 69 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या इसे रोका जा सकता है। दरअसल देश के ज्यादातर राज्यों में बाढ़ तबाही मचाती है। भारत विश्व का दूसरा बाढ़ प्रभावित देश है। बाढ़ आने के तीन

प्रमुख कारण यह है कि- पहला तो ये है कि जो नदियां होती हैं उनके तल में कुछ अवसर पैदा हो जाए तो उससे क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, दूसरा कारण यह है कि बांध नहीं बनाए जाते हैं और नदियों में अगर जल की अधिकता होती जाए और उसके पानी को नहीं निकाला ना जाए स्टार्ट न किया जाए तो बाढ़ आने का एक कारण यह भी होता है और तीसरा है कि बारिश हद से अधिक हो जाए।

हम कह सकते हैं कि यह बाढ़ भले ही प्राकृतिक आपदा रही हो लेकिन कहीं न कहीं इस आपदा के पीछे मानवीय गलतियों

की भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। बाढ़ चंबल, सिंधु और सहायक नदियों में आयी थी। हम जानते हैं कि ज्यादा बारिश होने के कारण इन नदियों पर बने बांधों से लगातार पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ना मजबूरी थी। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बाढ़ मानवनिर्मित नहीं होती है।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले साढ़े 6 दशकों के दौरान बाढ़ से सालाना औसतन 1,654 लोगों की मौत हुई और 92,763 पशुओं की जान गई। इससे सालाना औसतन 71.69 लाख हैक्टेयर इलाके पर असर पड़ा और तकरीबन 1,680 करोड़ रुपए की फ़सलें

तबाह हो गईं। बाढ़ से सालाना 12.40 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा। साल 1953 से 2017 के कुल नुकसान पर नज़र डालें, तो देश में बाढ़ की वजह से 46.60 करोड़ हैक्टेयर इलाके में 205.8 करोड़ लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस दौरान 8.06 करोड़ मकानों को नुकसान पहुंचा है। अफसोस की बात है कि हर साल बाढ़ से होने वाले जान व माल के नुकसान में बढ़ोतारी हो रही है, जो बेहद चिंताजनक है।

पिछले 07 दशकों में देश में अनेक बांध बनाए गए हैं, साथ ही पिछले क़रीब 3 दशकों से बाढ़ नियंत्रण में मदद के लिए रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया जा रहा है,

लेकिन संतोषजनक नतीजे सामने नहीं आ पा रहे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए 1978 में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। देश के कुल 32.9 करोड़ हैक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित इलाके में आती है। देश में हर साल तकरीबन 4,000 अरब घनमीटर बारिश होती है। हैरत की बात यह भी है कि बाढ़ एक राष्ट्रीय आपदा है, इसके बावजूद इसे राज्य सूची में रखा गया है। इसके तहत केंद्र सरकार बाढ़ से संबंधित कितनी ही योजनाएं बना ले, लेकिन उन पर अमल करना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। प्रांतवाद के कारण राज्य बाढ़ से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर पाते। एक राज्य





की बाढ़ का पानी समीपवर्ती राज्य के इलाकों को भी प्रभावित करता है। मसलन हरियाणा का बाढ़ का पानी राजधानी दिल्ली में छोड़ दिया जाता है जिससे यहाँ के इलाके पानी में डूब जाते हैं।

राज्यों में हर साल बाढ़ की रोकथाम के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, मगर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से इन योजनाओं पर ठीक से अमल नहीं हो पाता। नतीजतन, यह योजनाएं महज कागजों तक ही सिटटकर जाती हैं। हालांकि बाढ़ को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांध बनाना, नदियों के कटान वाले इलाकों में कटान रोकना, पानी की निकासी वाले नालों की सफाई और उनकी सिल्ट निकालना, निचले इलाकों के गांवों को ऊंचा करना, सीवरेज व्यवस्था को

सुधारना और शहरों में नालों के रास्ते आने वाले कब्ज़ों को हटाना आदि शामिल हैं।

बाढ़ से नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल

गौरतलब है कि बांग्लादेश के बाद भारत ही दुनिया का दूसरा सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त देश है। देश में कुल 62 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं जिनमें से 18 ऐसी हैं, जो अमूमन बाढ़ग्रस्त रहती हैं। उत्तर-पूर्व में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरप्रदेश तथा दक्षिण में आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु बाढ़ग्रस्त इलाके माने जाते हैं, लेकिन कभी-कभार देश के अन्य राज्य भी बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मयूराक्षी, अजय, मुंडेश्वरी, तीस्ता और तोसा नदियां तबाही मचाती हैं। ओडिशा में सुर्वारेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानंदा, ऋषिकुल्या,

वामसरदा नदियां उफान पर रहती हैं। आंध्रप्रदेश में गोदावरी और तुंगभद्रा, त्रिपुरा में मनु और गुमती, महाराष्ट्र में वेणगंगा, गुजरात और मध्यप्रदेश में नर्मदा नदियों की वजह से इनके टट्टवर्ती इलाकों में बाढ़ आती है। बाढ़ से हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन नुकसान का यह अंदाज़ा वास्तविक नहीं होता। बाढ़ से हुए नुकसान की सही राशि का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है, क्योंकि बाढ़ से मकान व दुकानें क्षतिग्रस्त होती हैं। फसलें तबाह हो जाती हैं। लोगों का कारोबार ठप हो जाता है। बाढ़ के साथ आने वाली बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी काफ़ी पैसा ख़र्च होता है। लोगों को बाढ़ से नुकसान की भरपाई में काफ़ी वक्त लग जाता है। यह कहना ग़लत न होगा कि बाढ़ किसी भी देश, राज्य या व्यक्ति को कई

साल पीछे कर देती है। बाढ़ से उसका आर्थिक और सामाजिक विकास हर जाता है। इसलिए बाढ़ से होने वाले नुकसान का सही अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है।

बाढ़ नियंत्रण के उपाय कारण और निवारण

भारत में घटित होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक घटनाएँ बाढ़ की हैं। यद्यपि इसका मुख्य कारण भारतीय मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा ऋतु के चार महीनों में भारी जलप्रवाह है, परंतु भारत की असमित भू-आकृतिक विशेषताएँ विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की प्रकृति तथा तीव्रता के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं। बाढ़ के कारण समाज का सबसे गरीब तबका प्रभावित होता है। बाढ़ जान-माल की क्षति के साथ-साथ प्रकृति को भी हानि पहुँचती है। अतः सतत् विकास के नज़रिये से बाढ़ के आंकलन की ज़रूरत है। सामान्यतः भारी वर्षा के बाद जब प्राकृतिक जल संग्रहण स्रोतों/मार्गों की जल धारण करने की क्षमता का संपूर्ण

दोहन हो जाता है, तो पानी उन स्रोतों से निकलकर आस-पास की सूखी भूमि को डूबा देता है। लेकिन बाढ़ हमेशा भारी बारिश के कारण नहीं आती है, बल्कि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही कारणों का परिणाम है। जहाँ संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बाढ़ एवं सूखे जैसी जल संबंधी आपदाओं को रोकने के लिये हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये, वहीं बाढ़/सूखे से निपटने के लिये तत्र सहित पूर्व तैयारी जैसे विकल्पों पर जोर दिया जाना चाहिये। साथ ही प्राकृतिक जल निकास प्रणाली के पुनर्स्थापन पर भी अत्यधिक ज़ोर दिये जाने की आवश्यकता है।

बाढ़ों का नियंत्रण- बाढ़ों को कई प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। वृक्षारोपण करके, बहकर आने वाले जल की मात्रा कम करने से बाढ़ के पानी का स्तर भी घट जायेगा। जंगल बारिश के पानी को भूमि के अंदर जाने का रास्ता देते हैं। इससे भूमिगत जल स्तर पुनः स्थापित होता

है और पानी का व्यर्थ बहना कम हो जाता है। बांधों के निर्माण से पानी का भंडारण होता है और बाढ़ के जल में कमी आती है। बांध पानी को एकत्रित कर सकते हैं, इस कारण पानी नीचे नदियों तक नहीं पहुँच पाता। यदि बांध में एकत्रित पानी सीधा नदियों तक पहुँचे तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। बांधों से पानी को नियंत्रित रूप में छोड़ा जाता है। नदी/नहर/नालों से गाद निकालकर उन्हें गहरा करने से और तटों को चौड़ा करने से उनमें अधिक पानी भरने की धारण क्षमता बढ़ जाती है। यदि बाढ़ नियंत्रण की उचित योजना और उचित प्रबन्धन तरीकों का नियोजित ढंग से पालन करें तो बाढ़ से होने वाली क्षति और जान-माल की हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है और कम किया जा सकता है।

हमारे देश में भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। इसके लिए जहाँ प्रशासन को चाक-चौबंद रहने की ज़रूरत है, वहीं जनमानस को भी प्राकृतिक आपदा से निपटने का





प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। स्कूल-कॉलेजों के अलावा जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है। इस तरह प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

बिहार और असम में कुदरत के कहर ने मानवता को कराहने पर विवश कर दिया है। सैकड़ों लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। सैकड़ों लोग लापता है, हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। बहरहाल, जो लोग बाढ़ की विभीषिका से बच गए हैं, उनका हृदय अपनों को खोने के बाद तड़प रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े सभी को प्रलय का एहसास हो रहा है। कई दिनों से पानी के बीच रहकर भी लोग घ्यास से तड़प रहे हैं। जाति धर्म से परे सभी लोग इसका दंश झेलने को मजबूर हैं। जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है और ना जाने कब तक लोग इस दर्द को झेलते

रहेंगे। जिन्होंने अपने स्वजनों और आसपास के लोगों को खोया है, उनके आंसू शायद ही कभी बंद हों। दुःखों के इस पहाड़ टूटने की घड़ी में सेना, एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि बचाव कार्य में लगे हुए हैं, वह काबिले तारीफ है।

नदियों का छोटा होता बेसिन, नदारद होते तटबंध और प्रवाह क्षेत्र में मानवीय अतिक्रमण बाढ़ के रूप में बड़ी समस्या बनकर उभरते हैं। अकेले बाढ़ से पिछले 20 सालों में 547 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। इतने में देशभर में ढाई लाख से ज्यादा स्कूल खोले जा सकते थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1953 से 2017 के बीच बाढ़ की वजह से गुजरे 64 सालों में 1,07,487 लोगों की जान चली गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, सच तो यह है कि हम इस तरह के हादसों को देखने के आदि हो चुके हैं। सरकारें बचाव कार्य और राहत पहुंचाकर अपने

कर्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं। बाद में सब भूल जाते हैं। इस साल बिहार और असम इस समस्या से जूझ रहा है, अगले साल किसी दूसरे राज्य के लोग अपनी खुशियां तबाह करने मजबूर होंगे? फिर सरकारी खजाने से लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। यह समय नसीहत देने और बयानबाजी का नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे विकास रूपी माथे पर कलंक हैं।

ये सही है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता लेकिन मानव जीवन और धन हानि को प्रयासों से नियंत्रण में किया जा सकता है। पहले देश में बड़े-बड़े अकाल होते थे जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा देते थे। वह भी प्राकृतिक आपदाएं ही रहती थी। हमारी सरकारों ने अथक प्रयास कर अकाल जैसी परेशानियों पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे ही अगर हम सच्चे मन के प्रयासों से इस कार्य में जुटेंगे तो हम इस मुसीबत से भी निजात पा

लेंगे। जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने की तत्परता दिखाई थी। लेकिन किन्हीं कारणों से यह योजना सफल नहीं हो सकी। बाढ़ से बचने के लिए केवल नदियों को जोड़ना एकमात्र हल नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां करनी होंगी।

दरअसल, नियंत्रण और बचाव का प्रयास एक दिन में संभव नहीं। देश में चर्चा सिर्फ बाढ़ के बाद हुई तबाही के दौरान ही होती है, जबकि पूरे साल अगर इससे निपटने के उपायों पर चर्चा के साथ योजनाएं बनें तो काफी कुछ हासिल हो सकता है। बाढ़ सिर्फ चुनौती के रूप में नहीं ली जानी चाहिए। चुनौती तो यह सरकारी कुप्रबंधन से होती है। सरकारें बाढ़ से निपटने के लिए चुनिंदा विशेषज्ञों से राय ले समस्या से निपटना चाहती हैं जबकि बाढ़ संभावित क्षेत्र की जनता से भी संवाद होना चाहिए। प्रयास हो कि कृषि प्रधान भारत में बाढ़ चुनौती के बजाए संभावना का सबव

बने। यदि समय रहते उससे निपटने के उपाय तलाश लिये जाएं तो पानी उतर जाने के बाद उपजाऊ क्षेत्र का अधिकाधिक इस्तेमाल हो सकता है।

भारत के विभिन्न राज्यों में बाढ़

भारत के विभिन्न राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण जान-माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हैंकेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज्यादातर नदियाँ, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ के कारण पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसूनी वर्षा की तीव्रता तथा मानव कार्यकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच लौटे मानसून से होने

वाली तीव्र वर्षा द्वारा आती है।

बाढ़ का परिणाम

असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश (मैदानी क्षेत्र) और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात एवं हरियाणा में बार-बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के ढूबने से देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढाँचा, जैसे- सड़कें, रेल मार्गों, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुँचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियाँ, जैसे- हैजा, आंत्रशोथ, ऐपेटाइटिस एवं अच्य दूषित जलजनित बीमारियाँ फैल जाती हैं। दूसरी ओर बाढ़ के कुछ लाभ भी हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिठी जमा करती है जो फसलों के लिये बहुत लाभदायक है।

बाढ़: राज्य सूची का विषय है
कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का



विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। बाढ़ प्रबंधन एवं कटाव-रोधी योजनाएँ राज्यन सरकारों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार अपने संसाधनों द्वारा नियोजित, अन्वे षित एवं कार्यान्वित की जाती हैं। इसके लिये केंद्र सरकार राज्योंव को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय जल नीति 2012 (बाढ़ एवं सूखे का प्रबंधन)

जहाँ संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बाढ़ एवं सूखे जैसे जल संबंधी आपदाओं को रोकने के लिये हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये, वहीं बाढ़/सूखे से निपटने के लिये तंत्र सहित पूर्व तैयारी जैसे विकल्पों पर ज़ोर दिया जाना चाहिये। साथ ही प्राकृतिक जल निकास प्रणाली के पुनर्स्थापन पर भी अत्यधिक ज़ोर दिये जाने की आवश्यकता है।

सूखे से निपटने के लिये विभिन्न कृषि कार्यानीतियों को विकसित करने तथा मृदा एवं जल उत्पादकता में सुधार के लिये स्थानीय, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक संस्थानों से प्राप्त वैज्ञानिक जानकारी सहित भूमि, मृदा, ऊर्जा एवं जल प्रबंधन की व्यवस्था की जानी चाहिये। आजीविका सहायता और गरीबी उपशमन के लिये समर्केति खेती प्रणालियों और गैर-कृषि विकास पर भी विचार किया जा सकता है।

नदी द्वारा किये गए भूमि कटाव जैसे स्थायी नुकसान को रोकने के लिये तटबंधों इत्यादि के निर्माण हेतु आयोजना, निष्पादन, निगरानी भू-आकृति वैज्ञानीय अध्ययनों के आधार पर किया जाना चाहिये। चूँकि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक तीव्र वर्षा होने तथा मृदा कटाव की संभावना बढ़ने से यह और भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

बाढ़ का सामना करने के लिये तैयार रहने हेतु बाढ़ पूर्वानुमान अति महत्वपूर्ण है।



तथा इसका देश भर में सघन विस्तार किया जाना चाहिये और वास्तविक समय ऑकड़ा संग्रहण प्रणाली (Real Time Data Collection System) का उपयोग करते हुए आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये। साथ ही इसे पूर्वानुमान मॉडल से जोड़ा जाना चाहिये। पूर्वानुमान समय को बढ़ाने के लिये विभिन्न बैरिंग भागों हेतु भौतिक मॉडल विकसित करने के प्रयास किये जाने चाहिये।

जलाशयों के संचालन की प्रक्रिया को विकसित करने तथा इसका कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिये ताकि बारिश के मौसम के दौरान बाढ़ को सहन करने संबंधी क्षमता प्राप्त हो सके और अवसादन के असर को कम किया जा सके। ये प्रक्रियाएँ ठोस निर्णय सहयोग प्रणाली पर आधारित होनी चाहिये।

बाढ़ प्रवण (Prone) तथा सूखा प्रवण समस्त क्षेत्रों का संरक्षण करना व्यवहार्य नहीं हो सकता; अतः बाढ़ तथा सूखे से निपटने के लिये पद्धतियों को बढ़ावा दिया

जाना आवश्यक है। बाढ़ से निपटने की कार्यानीतियों को विकसित करने के लिये बारंबारता आधारित बाढ़ आप्लाईन मानचित्रों को तैयार किया जाना चाहिये जिसमें बाढ़ के दौरान एवं इसके तुरंत बाद सुरक्षित जल की आपूर्ति करने की पूर्व तैयारी शामिल है। बाढ़/सूखे की स्थितियों से निपटने के लिये कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया में समुदायों को शामिल किये जाने की आवश्यकता है।

आकस्मिक बाढ़ से संबंधित आपदाओं से निपटने के लिये तैयारी हेतु प्रभावित समुदायों को शामिल करते हुए बांध/टटबंध क्षति संबंधी अध्ययन किये जाने चाहिये तथा आपातकालीन कार्रवाई योजनाओं/आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार किया जाना चाहिये और इन्हें आवधिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिये। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लोशियर, झील टूटने से बाढ़ तथा भू-स्खलन और बांध टूटने से बाढ़ आने संबंधी अध्ययन किये जाने चाहिये और यंत्रीकरण आदि सहित

बीजेपी के लिए क्या तुरुप का इक्का साबित होंगे धनखड़?

आखिर इस फैसले से बीजेपी किस वर्ग को साधने की कर रही कोशिश



समता पाठक

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना कर एक बार फिर चौंका दिया है। ममता बनर्जी का मुकाबला करने की क्षमता और जाट नेता होने की वजह से धनखड़ भाजपा के लिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में पहली पसंद बने। इनको प्रत्याशी बनाने के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, एक तरफ तो देश की लगभग 44 फीसदी आबादी यानी कि पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की है। तो वहाँ दूसरी तरफ मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भी बीजेपी ने सबक सिखा दिया है।

दूसरी तरफ हरियाणा, राजस्थान और

उत्तर प्रदेश के जाट बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इनको साधने के लिए धनखड़ तुरुप को इक्का साबित हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से हो सकता है कि कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान नाराज थे, उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाए।

वहाँ केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रहे मणिपुर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भी एक तरीके सबक सिखा दिया गया है। आइए जानते हैं धनखड़ को मैदान में उतारकर बीजेपी को क्या फायदा होगा?

राजस्थान में कई विस सीटों पर जाटों का दबदबा

राजस्थान में कुल आबादी के करीब के 10 प्रतिशत जाट हैं। राज्य में इनकी कुल

आबादी करीब डेढ़/दो करोड़ है। राज्य के सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू समेत बहुत से जिलों में जाटों की काफी अच्छी जनसंख्या है।

राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में औसतन 20 फीसदी विधायक जाट होते हैं। वहाँ 30/40 सीटों पर जाट जाति का प्रत्याशी ही चुनाव जीतता है। वहाँ पांच लोकसभा सीटों पर भी जाट वोट बैंक काफी मजबूत है। 2023 नवंबर और दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में धनखड़ के जरिए भाजपा राजनैतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी।

हरियाणा में रुठे जाटों को मनाने की कोशिश

जाट समाज की आबादी हरियाणा में 18/20 प्रतिशत है। जिसके चलते राज्य की विधानसभा और लोकसभा सीटों पर जीत हार को जाट समाज का सीधे तौर पर प्रभावित करता है। कृषि कानून के चलते जयादातर जाट समाज के किसान नाराज थे। बीजेपी उम्मीद लगा रही है कि धनखड़ को प्रत्याशी बनाए जाने से जाट समाज की नाराजगी शायद दूर हो जाए।

यूपी में पकड़ मजबूत करने की काव्यद

उत्तर प्रदेश में जाट समाज की आबादी 2 प्रतिशत है। किसानी से जुड़ा यह 2 फीसदी वर्ग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली वर्गों में से एक माना जाता है। विधानसभा चुनाव में इस वर्ग को साधने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। जिसका भाजपा को फायदा भी मिला। धनखड़ के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा इस वर्ग को फिर एक बार साधने की कोशिश कर रही है।

सत्यपाल मलिक को सबक सिखाने की कोशिश

सत्यपाल मलिक जो वर्तमान में मेघालय के गवर्नर हैं, वे बीते तकरीबन दो साल से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। किसान आंदोलन के वक्त भी मलिक किसानों का पक्ष लेते नजर आए थे। जम्मू कश्मीर और गोवा के गवर्नर रहते उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर ऐसी बातें कहीं, जिससे बीजेपी और उसके नेतृत्व की किरकिरी हुई। लेकिन अब बीजेपी के धनखड़ को उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनाने के बाद माना जा रहा है कि मलिक को बीजेपी ने किनारे कर दिया है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार होंगी मार्गरेट अल्वा; गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखण्ड की रह चुकी राज्यपाल



कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार होंगी। वह अल्वा राजस्थान, गोवा, गुजरात और उत्तराखण्ड की राज्यपाल रह चुकी हैं। मार्गरेट अल्वा की उम्र 80 साल है। उनकी उम्मीदवारी का ऐलान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की। विपक्षी दलों के नेताओं ने 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के चयन को लेकर 17 जुलाई को दिल्ली में बैठक बुलाई थी। शरद पवार के आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल, राजद, समाजवादी पार्टी सहित सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया।

मार्ग्रेट अल्वा कौन हैं ?

मार्ग्रेट अल्वा का जन्म 14 अप्रैल 1942 को मंगलुरु में हुआ था। अल्वा की पढ़ाई बंगलुरु में हुई। 24 मई 1964 में उनकी शादी निरंजन अल्वा से हुई। उनकी एक बेटी और तीन बेटे हैं। निरंजन अल्वा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारतीय संसद की पहली जोड़ी जोकिम अल्वा और वायलेट अल्वा के पत्र हैं। अल्वा 1974 में

पहली बार राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। उन्होंने छह-छह साल के चार कार्यकाल लगातार पूरे किए। मार्गरेट अल्वा राजीव गांधी और पीवी नरसिंहा राव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। इसके बाद वे 1999 में वे लोकसभा के लिए चुनी गईं। उन्हें 1984 में संसदीय कार्य राज्यमंत्री और बाद में युवा मामलात और खेल, महिला एवं बाल विकास के प्रभारी का दायित्व संभाला। 1991 में उन्हें कार्मिक, पेशन, जन अभाव अभियोग और प्रशासनिक सुधार राज्यमंत्री का जिम्मा दिया गया था।

रह चुकी हैं 4 राज्यों की राज्यपाल

मार्गरेट अल्वा को 42 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। वह राजीव गांधी और पीवी नरसिंहा राव के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री बनीं। 2008 में उन्होंने कर्नाटक चुनावों में टिकट बेचे जाने की बात कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। मार्गरेट अल्वा ने गोवा, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखण्ड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है।

विपक्ष ने क्यों अपनाई वेट एंड वॉच रणनीति

माना जा रहा है कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा के लिए वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई है। ऐसा इसलिए किया गया क्यों कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों ने राजगद्वारा द्वौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का ऐलान किए जाने से पहले ही यशवंत सिन्हा को अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इससे शिवसेना, यूपी की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी सुभाषणा और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा समेत कई अन्य गैर-बीजेपी दलों ने बाद में यशवंत सिन्हा के बजाय द्वौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की थी।

नगरीय निकाय चुनाव परिणाम....

कांग्रेस ने बिछा दी 2023 की विसात

कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में जीती पांच मण्डपौर की सीटें



वैसे देखा जाए तो नगर निगम परिणाम बीजेपी और कांग्रेस के लिए बराबर ही रहे हैं। क्योंकि उज्जैन में कांग्रेस के महेश परमार बीजेपी के मुकेश टट्टवाल से सिर्फ 736 वोट से हारे। जबकि बुरहानपुर में बीजेपी की माधुरी पटेल ने कांग्रेस की शहनाज अंसारी को महज 542 वोटों से हराया। विधानसभा चुनाव से पहले बड़े शहरों में जीत कांग्रेस का कमबैक कहा जा रहा है। साल 2015 के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने मेयर पद की सभी 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष के 97 पदों के निर्वाचन में 53 पर बीजेपी ने और 39 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। सबसे चौंकाने वाला नतीजा सिंगरौली और कटनी का रहा। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की मेयर बनी। कटनी में जनता ने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ी प्रत्याशी को मेयर चुना। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हुआ है।

विजया पाठक

मध्यप्रदेश में सात साल बाद हुए नगरीय निकाय और नगर परिषद के चुनावों के परिणाम सामने आ गए हैं। इस बार के चुनावों में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। 57 साल से ग्वालियर सीट पर जमी बैठी भाजपा को कांग्रेस पार्टी ने महापौर की सीट से बेदखल कर दिया। ऐसा ही कुछ हाल रीवा में देखने को मिला जहां 24 साल बाद कांग्रेस पार्टी का

परिणामों में भोपाल इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, सागर और सतना में भाजपा ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने जबलपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा पर कब्जा जमाया। सिंगरौली से आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल महापौर चुनी गई। दूसरे चरण के परिणाम में कांग्रेस ने मुरैना और रीवा, बीजेपी से 1-1 सीट छीन ली बीजेपी के खाते में रत्लाम और देवास की 1-1 सीट ही आई है। पिछले चुनाव में ये

उज्जैन में कांग्रेस के महेश परमार बीजेपी के मुकेश टट्टवाल से सिर्फ 736 वोट से हारे। जबकि बुरहानपुर में बीजेपी की माधुरी पटेल ने कांग्रेस की शहनाज अंसारी को महज 542 वोटों से हराया। विधानसभा चुनाव से पहले बड़े शहरों में जीत कांग्रेस का कमबैक कहा जा रहा है। साल 2015 के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने मेयर पद की सभी 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष के 97 पदों

महापौर की 16 में से बीजेपी 09, कांग्रेस 05, आप 01 और 01 सीट पर निर्दलीय जीतें

प्रत्याशी महापौर पद के लिए चुना गया। जबलपुर, ग्वालियर चंबल, कटनी, सिंगरौली जैसी सीटों पर पर भी भाजपा को शिकस्त मिली। इन आंकड़ों के बाद तस्वीर साफ है कि जो भाजपा सात साल पहले 16 नगरीय निकायों में सभी सीटों पर कब्जा जमाए बैठी हुई थी। वो अब 9 सीट पर आ गई है। कांग्रेस को पांच, 1-1 सीट आप पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी को मिली। पहले चरण में 11 नगर निगम के आये

पांचों मेयर सीट बीजेपी को मिली थी। साफ कहा जाए तो बीजेपी मालवा छोड़ विध्य और चंबल में सीट ही नहीं बचा सकी। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। 16 नगर निगमों में बीजेपी के 09, कांग्रेस के 5 महापौर प्रत्याशी जीते हैं। आम आदमी पार्टी ने 1 और 1 निर्दलीय महापौर बने हैं। वैसे देखा जाए तो नगर निगम परिणाम बीजेपी और कांग्रेस के लिए बराबर ही रहे हैं। क्योंकि

के निर्वाचन में 53 पर बीजेपी ने और 39 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। सबसे चौंकाने वाला नतीजा सिंगरौली और कटनी का रहा। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की मेयर बनी। कटनी में जनता ने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ी प्रत्याशी को मेयर चुना। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हुआ है। पिछली बार से भाजपा को इस बार 07 सीट गंवाना पड़ी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य



सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने गढ़ नहीं बचा पाए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दो सभा करने के बाद भी रीवा में कांग्रेस का मेयर बन गया। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद दोनों बड़ी पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, इसे अपनी जीत बता रही हैं। कांग्रेस इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विफलता बता रही है तो बीजेपी का दावा है कि यह कांग्रेस की एक और हार है। दोनों पार्टियां इसे 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित जीत का आधार मान रही हैं। सच तो यह है कि इन नतीजों को किसी एक पार्टी की जीत के रूप में देखना अतिशयोक्ति होगी। कुछ आंकड़ों के जरिए नतीजों के असली मायने और भविष्य के लिए इसके निहितार्थ को समझा जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में मध्यप्रदेश में 16 नगर निगम, 378 नगर निकायों में और 23,023 ग्राम पंचायतों के

लिए चुनाव हुए हैं। वर्तमान में नगर निगमों की स्थिति तो साफ हो गई है लेकिन नगरपालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा यह कहना अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

कांग्रेस पार्टी को बड़ी कामयाबी

लगभग ढाई साल पहले सत्ता में लौटी कांग्रेस पार्टी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य

सिंधिया की गद्दारी के कारण अपनी सरकार गंवानी पड़ी। उस समय प्रदेश भाजपा ने सरकार गिरने का काफी जश्न मनाया। इस सभी बातों को प्रदेश की जनता ने करीब से देखते हुए यह समझने की कोशिश की भाजपा सत्ता के लालच में खरीद-फरोज़ तक उतर आई है। उस समय भाजपा की इस करतूत का बदला

नगर परिषदों में 255 में से 190 पर भाजपा का कब्जा

अगर परिषदों में 255 में से 190 पर भाजपा का कब्जा है। यह पिछली बार से 43 ज्यादा है। यह आंकड़ा इतना बड़ा होने की एक वजह 29 नई नगर परिषदें जुड़ना भी है। इनमें भी अधिकतर पर भाजपा की जीत हुई है। कांग्रेस नगर परिषदों में 60 से घटकर 35 पर आ गई है। निर्दलीय और तीसरे मोर्चे का बहुमत 30 सीटों पर दिखा है, यह पहले 45 हुआ करता

था। यहां भी कई सीटें अभी भी फंसी हुई हैं क्योंकि अधिकतर जगह निर्दलीय ही निर्णायक हैं। वे जिसके साथ जाएंगे, अध्यक्ष उसका ही होगा।



प्रदेश की जनता ने नगरीय निकाय और नगर परिषद के चुनाव में लिया। सात साल पहले जो भाजपा नगरीय निकाय चुनावों में 16 सीटों के साथ सीना तान खड़ी थी। आज उस भाजपा को प्रदेश की जनता ने 9 सीटों पर लाकर पटक दिया। कांग्रेस पार्टी 23 साल बाद प्रदेश में 5 महापौर लेकर पूरी हिम्मत के साथ खड़ी है। जनता से

मिले इस समर्थन के बाद यह साफ हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में उलटफेर की संभावना फिर से जाग्रत हो गई है।

भाजपा के लिए कांग्रेस बनेगी चुनौती

नगरीय निकाय के परिणामों को देखते हुए एक बात तो साफ हो गई है कि आगामी

विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में भाजपा को कड़ी टक्कर कांग्रेस से मिलेगी। आत्मविश्वास से भरपूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सारे मुगालते नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम में दूर हो गए हैं। भाजपा के अधिकतर नेता यही मानकर चल रहे थे कि पूरी 16 सीटें भाजपा जीत ही जाएंगी। जानकारों के अनुसार देखा जाए तो आगामी चुनाव में भाजपा को केवल कांग्रेस से ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी नुकसान होना तय है। अगर भाजपा के अंदर अब भी अंतरघात समाप्त नहीं हुआ तो निश्चित ही इसका भुगतान भाजपा को भुगतना पड़ सकता है।

कमलनाथ की मेहनत रंग लाई

देखा जाए तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ। कांग्रेस ने इस बार के नगरीय निकाय और नगर परिषद के चुनावों में काफी कुछ पाया। इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की कूटनीति, सधी हुई चाल

नगर पालिका में भाजपा का 76 में से 57 पर कब्जा

नगर पालिका की बात करें तो उसने 76 में से 57 पर कब्जा जमाने का मौका है जो कि पिछली बार से 4 सीट ज्यादा है। कांग्रेस के लिए कोई चेंज नहीं रहा। वह पहले भी 18 नगर पालिकाएं जीती थीं, इस बार भी यही आंकड़ा रहा। निर्दलीयों और तीसरे मोर्चे को इस बार सिर्फ 1 नगर पालिका में बहुमत मिला है। इनमें कई सीटें अभी भी फंसी हुई हैं क्योंकि अधिकतर जगह निर्दलीय ही निर्णयिक हैं। वे जिसके साथ जाएंगे, अध्यक्ष उसका होगा।

आंकड़ों में समझें स्थिति

- यह बीजेपी की जीत नहीं है क्योंकि सात नगर निगमों में पार्टी को मेरठ का पद गंवाना पड़ा है। सात साल पहले सभी १६ नगर निगम जीतने वाली पार्टी इसे अपनी जीत होने का दावा नहीं कर सकती।
- यह कांग्रेस की हार भी नहीं है क्योंकि पिछले चुनाव की तुलना में पार्टी के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। सात साल पहले के मुकाबले प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और कमजोर हुई है। इसके बावजूद यह कामयाबी उसके लिए उपलब्धि है।
- निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इनमें प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण उम्मीदवारों के मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध होते हैं। इसे जबलपुर के उदाहरण से समझा जा सकता है जहां बीजेपी प्रत्याशी को सीएम शिवराज और आरएसएस का पूरा समर्थन हासिल था। इसके बावजूद डॉ. जितेंद्र जामदार हार गए क्योंकि कोरोना काल में उनके खिलाफ कुछ आरोप लगे थे। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान हवा दी और जामदार के खिलाफ माहौल बनाने में सफल रही।
- नतीजों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की असफलता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निकाय चुनाव में प्रचार के लिए उन्होंने जहां ज्यादा ध्यान दिया, वहां बीजेपी को जीत मिली। शिवराज ने मालवा-निमाड़ क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया और बीजेपी को सबसे ज्यादा कामयाबी भी वहीं मिली।
- इसे कमलनाथ के नेतृत्व पर सवालिया निशान के रूप में भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वे इन चुनावों में कांग्रेस के एकमात्र स्टार प्रचारक थे। रतलाम को छोड़ दें तो उनके चुने हुए उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया। चुनाव की सारी रणनीति भी कमलनाथ ने ही तैयार की थी जो काफी हद तक सफल रही।
- निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के लिए स्पष्ट संदेश है कि उन्हें अपना घर तंदुरुस्त करने की जरूरत है। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में स्टार प्रचारकों के बिना भी कांग्रेस जीती क्योंकि पार्टी के नेता एकजुट थे। वे यह साबित करना चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिना भी कांग्रेस जीत सकती है। वहीं, इसी इलाके में बीजेपी को बड़ी हार मिली क्योंकि सिंधिया और तोमर के समर्थकों बीच एकजुटता नहीं थी।
- कांग्रेस हो या बीजेपी, निकाय चुनाव के नतीजों को सवा साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की गारंटी नहीं मान सकती। दोनों के लिए यह एक मजबूत आधार हो सकता है लेकिन कोई भी पार्टी निश्चिंत नहीं रह सकती। विपक्ष को कमजोर मानने की गलती दोनों के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है।

और बेहतर प्रबंधन है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का उनका जो सूत्र था निश्चित ही उसने कांग्रेस को एक बेहतर स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया।

सिंधिया के घर ग्वालियर में बीजेपी की हार

सिंधिया के होम टाउन ग्वालियर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। चंबल ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर का जादू नहीं चला। भाजपा का ग्वालियर चंबल सीट गंवाना अच्छे संकेत नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ग्वालियर के दो बड़े नेता सिंधिया और तोमर ने इस क्षेत्र में बिल्कुल मैहनत नहीं की दोनों ही दिल्ली में अपने मंत्रालयों में बैठकर केवल शासकीय सुविधाओं का सुख भोग रहे हैं। जिसका खामियाजा भाजपा को ग्वालियर चंबल सीट गवांकर चुकाना पड़ा। जबकि कमलनाथ अपने गृह नगर छिंदवाड़ा को जीतने में सफल रहे। ग्वालियर के महापौर



मप्र में स्थानीय निकाय के चुनावों में सियासी संस्थानों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी ग्वालियर में थी। यह दलबदल करके भाजपा में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है इसलिए यहां की हार जीत के छीटे उनके दामन पर आने ही थे।

की कुर्सी पर करीब सत्तावन साल बाद कांग्रेस की शोभा सतीश सिकरवार बैठने जा रही हैं।

मप्र में स्थानीय निकाय के चुनावों में सियासी संस्थानों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी ग्वालियर में थी। यह दलबदल करके भाजपा में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है इसलिए यहां की हार जीत के छीटे उनके दामन पर आने ही थे। दलबदल के बाद भाजपा में उनका कद लगातार बढ़ रहा है। अपने लोगों को शिवराज सरकार में मनमाफिक मंत्री बनवाने वाले सिंधिया खुद मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। पार्टी में बढ़ते कद के बीच अपने ही शहर में पार्टी का मेयर न बनवा पाना उनके माथे पर शिकन लाने वाली बात है।

बीजेपी और कांग्रेस का कैसा रहा था पिछला प्रदर्शन

सबसे पहले बात करें 2015 के नगरीय निकाय चुनाव की तो बीजेपी के शत प्रतिशत मेयर चुने गए थे। बीजेपी ने सभी 16 शहरों के मेयर पद पर कब्जा किया था। वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष के 97 पदों के निर्वाचन में 53 पर बीजेपी ने और 39 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी।

नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए हुए मुकाबले में बीजेपी ने 154 और कांग्रेस ने 96 सीटें जीती थीं। जिला पंचायत और जनपद पंचायत चुनाव के आंकड़े बीजेपी की तरफ झुके हुए थे। जिला पंचायत की 51 सीटों में से 40 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें ही मिली थीं। जनपद पंचायत अध्यक्ष के 313 पदों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी

ने 214 और कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थीं। **दिग्गजों को अपने ही क्षेत्रों में मिली चुनौती**

देखा जाए तो भाजपा के लिए नगरीय निकाय चुनाव इस बार बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन भाजपा नेता इस चुनौती को सही ढंग से समझ नहीं पाए और 16-0 के आंकड़े से सीधे 9-7 पर आकर गिरे। भाजपा की इस दुर्दशा का बड़ा कारण है भितरघात। पार्टी इस समय भितरघात से कई हद तक पीड़ित है। लेकिन दिल्ली पार्टी नेताओं के भय के कारण कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। सबसे अधिक भितरघात ग्वालियर-चंबल सीट पर है। जहां कभी भाजपा का एकक्षत्र राज हुआ करता था आज स्थिति यह है कि भाजपा अपनी महापौर की सीट भी वहां से नहीं बचा पाई। यही हाल जबलपुर क्षेत्र का है। महाकौशल भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन भाजपा नेताओं के आपसी विवाद और आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास के कारण यह सीट भी गंवानी पड़ी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के कटनी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वहां भी भाजपा हार गई। सीहोर में 35 नगर परिषदों की सीट पर 22 पर भाजपा ने

मध्य प्रदेश की 16 निगमों में मौजूदा स्थिति

भाजपा

उज्जैन, बुरहानपुर, सागर, सतना, इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम, खंडवा

कांग्रेस

छिन्दवाड़ा, मुरैना, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर

आम आदमी पार्टी

सिंगरौली।

निर्दलीय

कटनी

मध्यप्रदेश में तीसरी ताकत ने दिखाया दम

निकाय चुनाव परिणाम से तीसरी ताकत के संकेत मिले हैं। इस बार निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा राजनीतिक सरगर्मियां प्रदेश की सियासत में तीसरे दलों की एंट्री ने बढ़ाई, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती हैं। निकाय चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी और एमआईएम ने मध्यप्रदेश में जोरदार सियासी दस्तक दी। सपा-बसपा की बात करें तो ये दोनों की पार्टियां मप्र में महज अपनी उपस्थिति ही दर्ज कराते रही हैं। यही नहीं, इस बार तो भाजपा-कांग्रेस को निगम से लेकर वार्डों तक में निर्दलियों ने भी मात दे दी, कटनी से महापौर के लिए निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी ने बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस को भी कड़ा संदेश दिया कि भविष्य की राजनीति में उनके लिए निर्दलीय भी चुनौती बनेंगे।

आप को मिला महापौर तो एआईएमआईएम को मिले पार्षद- पंजाब में विधानसभा चुनाव में भिली जीत से लबरेज आम आदमी पार्टी और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इसेहादुल-मुस्लिमीन इस बार मप्र के चुनावी समर में थीं। इधर, हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा था। तीसरी ताकत की मौजदगी से भाजपा-कांग्रेस बेखबर थीं, उन्हें इनकी मौजूदगी सियासी पर्यटन लग रही थी, लेकिन जो नतीजे आए, उससे दोनों ही पार्टियों का तिलिस्म टूट गया। आम आदमी पार्टी ने ना केवल सिंगरौली नगर निगम में महापौर का चुनाव जीता, बल्कि प्रदेशभर में पार्टी के पार्षद भी जीते। गवालियर में आप प्रत्याशी रुचि वर्मा को 45 हजार वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रहीं। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के 41 पार्षदों ने जीत हासिल की है, उनमें से पांच प्रत्याशी सिंगरौली नगर निगम से जीते हैं, जबकि बाकी प्रदेश की विभिन्न नगरपालिका एवं नगर परिषद से आप के पार्षद चुनाव जीते हैं। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की के भी आधा दर्जन पार्षद जीत गए, कई शहरों में तो पार्टी ने अपनी सियासी ताकत का एहसास दूसरे दलों को करवा दिया। ओवैसी की पार्टी के दो पार्षद जबलपुर में जीते, जबकि खंडवा और बुरहानपुर में भी एक-एक पार्षद जीता। खरगौन नगर पालिका में भी 03 एआईएमआईएम प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। ओवैसी की पार्टी ने बुरहानपुर महापौर चुनाव में 10 हजार से ज्यादा वोट लेकर कांग्रेस का खेल बिगाढ़ दिया, जबकि कई जगहों पर पार्षदों का खेल भी एआईएमआईएम ने बिगाढ़। ओवैसी की नजर मध्य प्रदेश के 50 लाख यानी 6.57 प्रतिशत मुस्लिम आबादी पर है। वह बीजेपी के विरोध का ऐसा चेहरा बन चुके हैं, जिन्हें मुस्लिम आबादी का बड़ा समर्थन मिलता है।

2023 में चुनाव लड़ने की तैयारी- मप्र में जिस तरह से इन दोनों दलों ने निकाय चुनाव में एंट्री की है उससे यह बात स्पष्ट है कि डेढ़ साल बाद 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव मध्यप्रदेश राजनीति में यह पार्टियां चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगी। सिंगरौली में जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो खासे उत्साहित हैं। इधर, ओवैसी ने मध्यप्रदेश में भविष्य की राजनीति में आने की घोषणा कर भाजपा-कांग्रेस के लिए चुनौती पैदा कर दी है। केजरीवाल जहां भाजपा के लिए मुसीबत बनेंगे, वहीं ओवैसी कांग्रेस के वोट में सेंधमारी करेंगे। प्रदेश में तीसरी ताकत की एंट्री से सियासी चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी-कांग्रेस से इतर तीसरा विकल्प भी बनेगा। हालांकि, मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास को देखते हुए अभी कुछ कहना भी जल्दबाजी हो सकती है।

कब्जा तो किया, लेकिन इसके लिए भी भाजपा नेताओं को ऐड़ी-चोटी का जोर

लगाना पड़ा। सागर में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के कारण वहां के दो वरिष्ठ

स्थानीय नेताओं को भितरघात का शिकार होना पड़ा। भूपेंद्र सिंह खुद अकेले ही पूरी



शिवराज और कमलनाथ के हाथ में थी कमान

1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासनकाल में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे। साल 2003 तक कांग्रेस के शासनकाल में निकायों में कांग्रेस का दबदबा रहा। इसके बाद के 17 साल शिवराज सरकार ने राज किया। 2014-15 के बाद अब 07 साल के अंतराल के बाद हो रहे चुनाव में तगड़ा मुकाबला हो गया है। अपनी पसंद से टिकिट वितरण करके बीजेपी की कमान शिवराज ने अपने हाथों में रखी। वहीं कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ संभाला। जिन्होंने अधिकांश टिकिट अपने सर्वे के आधार पर बांटे थे। बीजेपी को सभी 16 नगर निगम बचाने के लिए ताकत लगानी पड़ी। कहा जा रहा था कि यह चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल हो सकता है।



चुनाव की तैयारी में जुटे रहे और अन्य नेताओं को पूछना जरूरी भी नहीं समझा। इसका खामियाजा भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।

रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा ने 9 हजार से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध व्यास को हराया। कांग्रेस का यहां

24 साल बाद सूखा समाप्त हुआ। सूत्रों के अनुसार रीवा महापौर का पद भी भाजपा को राजेंद्र शुक्ला की नाराजगी के कारण हारना पड़ा। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वायदे अनुसार सरकार बनने के दो साल बाद अभी तक राजेंद्र शुक्ला को मंत्री पद नहीं दिया। जिससे वे खासे नाराज हैं और इसकी

नाराजगी का बदला उन्होंने महापौर की सीट गवांकर लिया। जबकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद दो-दो बार वहां चुनावी सभा में गये, लेकिन जनता उनके हवा-हवाई वायदों के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसी और रीवा से भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया।

There is a fundamental error in the thinking of the Pandit Nehru

Pandit Deendayal Upadhyaya
[Organiser, 28 August, 1961]



The Merger of Nagar Haveli and Dadra into the Indian union is a move in the right direction. That the Government of India should have taken seven long years to make this simple decision only shows that mental

state of indecisiveness of the rulers. What Sardar Patel could do within days in the case of Janagadh, Pandit Nehru has taken years to accomplish. Besides the inordinate delay, there is a basic difference

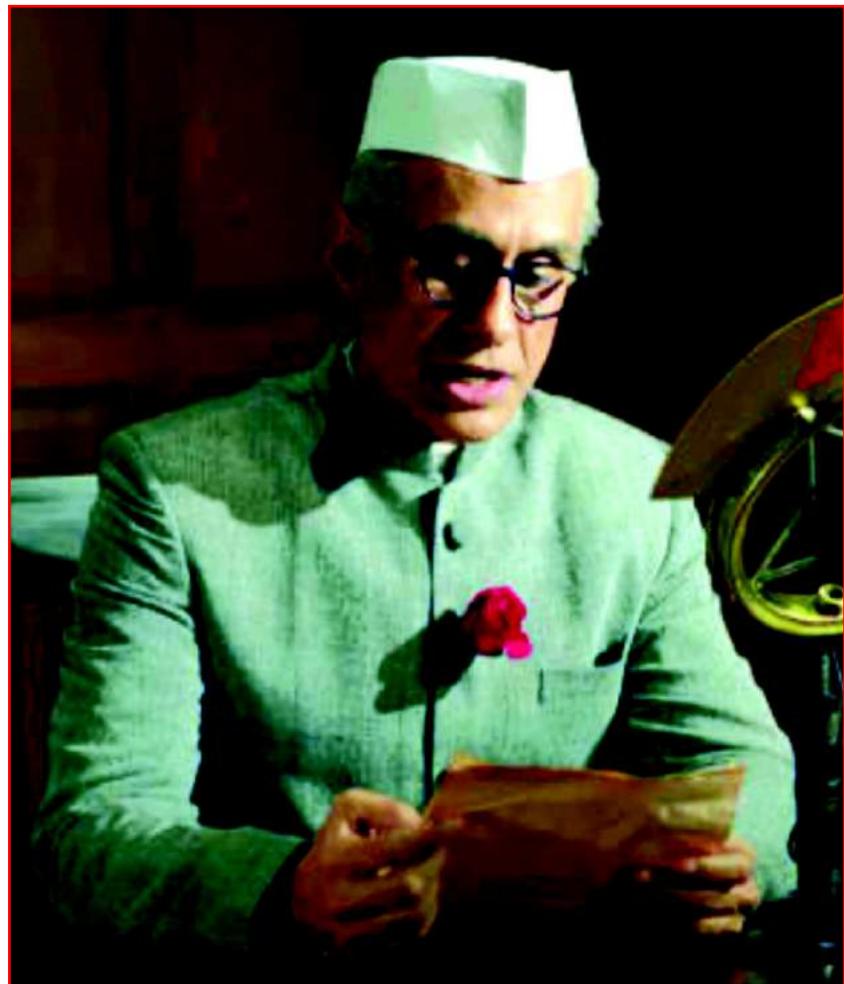
towards the issue of liberating, and integrating, areas laying outside the pale of considered it the Government's duty to actively work for their freedom and merger and he was his armoury to achieve his objective. Pandit Nehru it seems is not prepared to shoulder this responsibility. Neither is he prepared to go to the lengths to which Sardar Patel went in the case of Hyderabad.

Apart from temperamental weaknesses and hesitancy, there is a fundamental error in the thinking of the Prime Minister. He thinks within the frame-work of the Government of India Act of 1935 or the India Independence Act of 1946. The Sovereignty of India accordingly is limited to the territories handed over to her by the British and/or to States that join the dominion. In all other cases the people of the different areas are to be the architects of their fate and their future. If they desire to be independent, they must struggle. The status that they would enjoy is also to be determined by them. This line of thinking ignores the basic fact of India being one. It does not recognise the existence of an

Indian nation, which by historical accident came under the dominion of a number of Western powers. If the tiny territory of Goa was, and is ruled by Portugal while the rest of the country was under the British rule and now independent, it did not and does not in any way create a separate

Those who say that the people of Goa themselves should fight for their independence are propounding a theory which is dangerous and unnatural.

The merger of Nagar Haveli and Dadra has been effected in accordance with the wishes of the people of these areas. It is



Goanese people. The people of Goa are part and parcel of the Bharatiya Nation. The struggle for the liberation of these territories is therefore an integral part of our freedom struggle.

good and natural that these people have chosen to become part of the political set-up of the country. But any insistence on the right of these people to determine their future deprives

The Merger of Nagar Haveli and Dadra into the Indian union is a move in the right direction. That the Government of India should have taken seven long years to make this simple decision only shows that mental state of indecisiveness of the rulers. What Sardar Patel could do within days in the case of Janagadh, Pandit Nehru has taken years to accomplish.

the people of India their fundamental sovereignty over the whole land. It is on this account that the French enclaves in spite of their de facto transfer to India have not yet become part of the India union. The Government is waiting for a legal fiat by the French Government. Why should we look to the French for legalising the transfer? The territory is ours and if the French have given it peacefully, it can be credited to their good sense or common sense, but it cannot confer upon



Deendayal Upadhyaya : BJP's 'Gandhi' !

them any legal title to hold the areas even technically. Our Constitution gives us a right to acquire territories and we should act accordingly. Let the French take care of their Constitution. Let them amend or mend it, and at leisure. But we cannot delay the process of our national

integration.

Nagar Haveli and Dadra, like the French enclaves, have been kept as a separate unit. They are to be administered under the External Affairs Ministry. It is wrong. The areas should be straightway merged with the adjoining districts. That alone

will demonstrate our unity with these people.

With regard to Goa, the Bharatiya Jana Sangh had all along felt that the problem can be solved only by police action. It is a matter of satisfaction that the political opinion in the country has veered round to this

AKHAND BHARAT AND NATIONALISM

THE words 'Akhand Bharat' (un-divided India) include all those basic values of nationalism and an integral culture that the Jana Sangh has accepted. These words include the feeling that this entire land from Attock to Cutack, Kutch to Kamrup and Kashmir to Kanya Kumari is not only sacred to us but is a part of us. The people who have been born in it since times immemorial and who still live in it may have all the differences superficially brought about by place and time, but the basic unity of their entire life can be seen in every devotee of Akhand Bharat.



Shri Bala Saheb Deoras of R.S.S., Shri Atal Bihari Vajpayee, Rajmata Vijaya Raje Scindia and others on the occasion of the doundation laying ceremony of houses for Deendayal Dham service projects of Nagla Chandrahan on 13 July, 1982

view. Even the Prime Minister, who had all these years persistently refused to take resort to military force, has said that military action cannot be ruled out. It is a major change in the Government's policy and is in the correct direction. For the first time after Sardar Patel, Government spokesmen have asserted that the military can be used for the purpose which it is being maintained for. But there is a feeling in the people that all this talk is meant only to please the electorate.

The stiffness on the Goa issue is also meant to divert the attention of the people from the

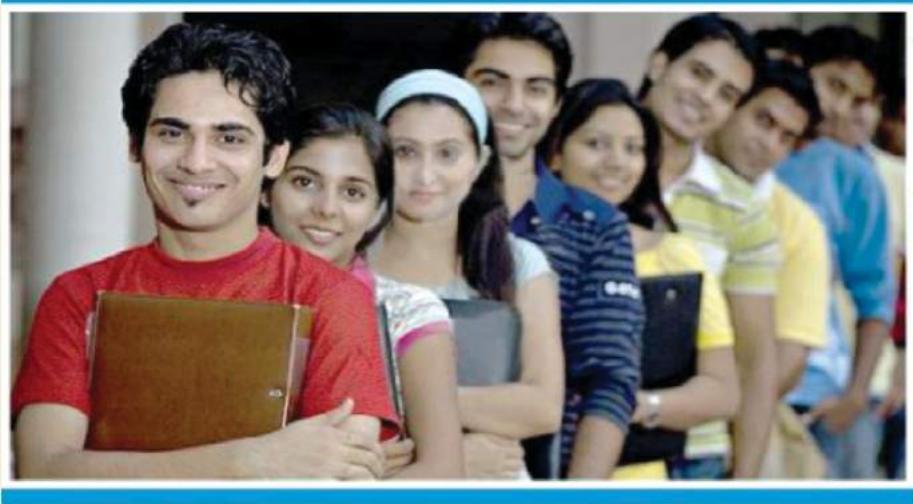
Government's failure on other fronts, notable the China and the Pakistan fronts. It is for this reason that the communists who had practically forgotten Goa have again become active and a new committee headed by Srimati Aruna Asaf Ali has been formed.

Whatever be the motive, liberation of Goa is desired by all. But when shall the Government do it? Will they take some active steps or simply fight a verbal battle? The people, who have been accustomed to such declarations, will not feel satisfied without any practical steps. Pandit Nehru will be wrong

if he thinks that he can dupe the nation simply be verbal assurances. Let him fulfil his assurances not within his lifetime but before the elections if he wants to reap its advantages for his party.

Even before steps for the liberation of these territories are taken, it would be desirable that the Goans living in the Indian union are granted Citizenship and franchise rights. It will establish our bona fide and demonstrate that we look upon these people as part and parcel of our nation.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल



जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :
मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

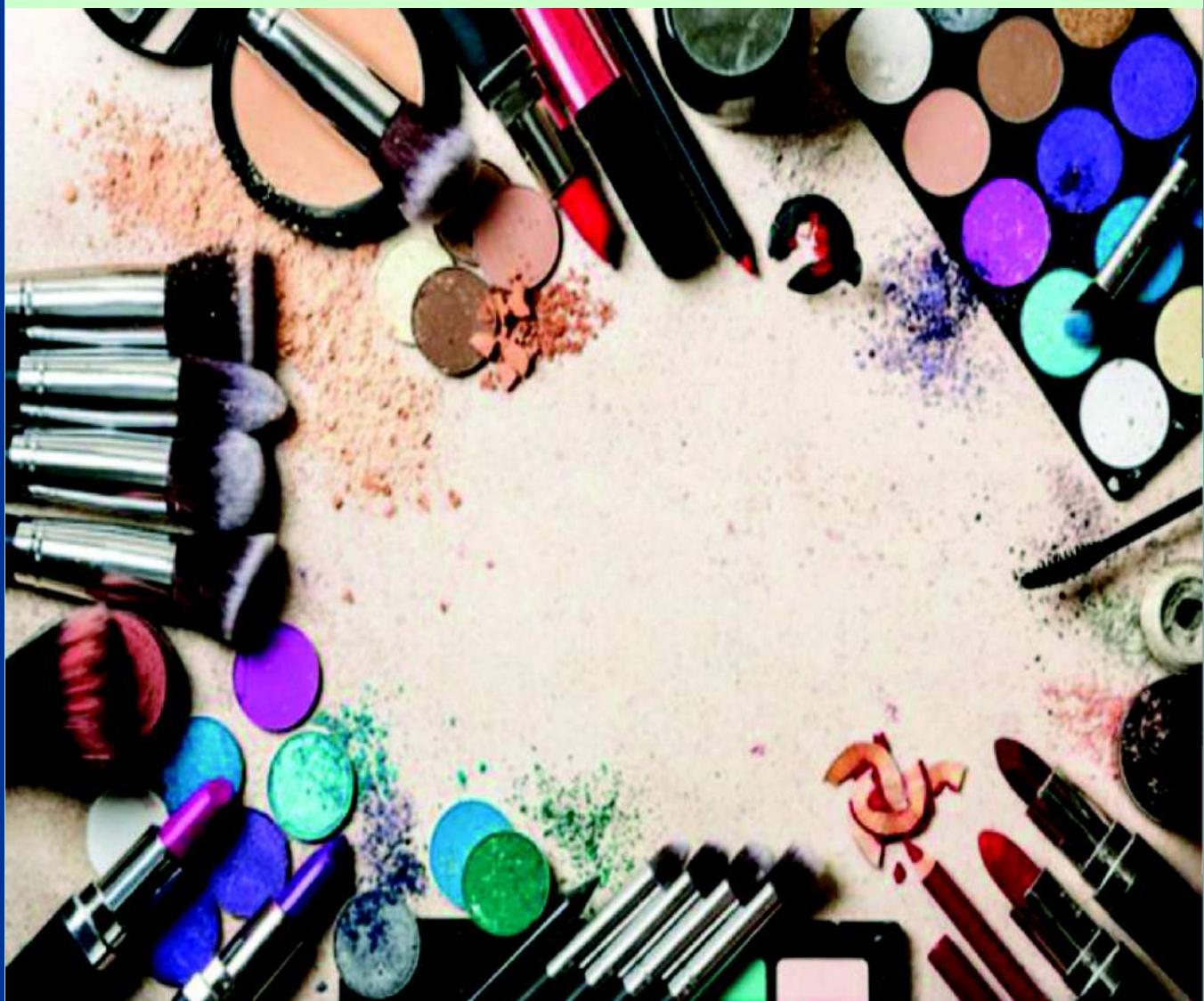
संपर्क सूचा

विजय पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.
संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

SAWARNA COSMETICS



**SHOP NO. 101/152, NEW MARKET,
BHOPAL, M.P. 462016**

उनहित के लिए जारी

सावधानी से गाड़ी चलाएं
या आप उसी जगह पहुंच जाएंगे
जहाँ जाना नहीं चाहते हैं।



निधि ट्रस्ट